वर्ष 12 • अंक 288 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 21 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

कौशिक चटर्जी ▶▶ पृष्ठ 3

भविष्य के लिए बढ़त का नया क्षेत्र होगा खनन

जगत प्रकाश नड्डा ▶▶ पृष्ठ 14

नड्डा को मिली भाजपा की कमान

डॉलर रु. 71.10 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 78.80 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39951 ▲ 142 रुपये | सेंसेक्स 41528.90 ▼ 416.50 | निफ्टी 12224.50 ▼ 127.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 12263.20 ▲ 38.60 | ब्रेंट क्रूड 65.00 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

तेल की तेजी पर फिसला सेंसेक्स और निफ्टी

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन बाद में इसने तेजी गंवा दी और 416.46 अंक गिरकर 41,528.91 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 127.80 अंक गिरकर 12,224.55 पर बंद हुआ। लीबिया में दो बड़े तेल उत्पादक ठिकानों के बंद होने से तेल के दाम फिर 65 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया।

आईएमएफ ने घटाया भारत का वृद्धि दर अनुमान

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 4.8 फीसदी कर दिया है, जो सरकार के अग्रिम अनुमान 5 फीसदी से भी कम है। आईएमएफ का ताजा अनुमान उसके पहले के अनुमान से 1.3 फीसदी कम है। इसके साथ ही आईएमएफ ने अनुमान जाहिर किया कि अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 5.8 फीसदी रह सकती है। आईएमएफ के अनुसार 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1.9 फीसदी रहेगी। पृष्ठ 4

यूनिटेक प्रबंधन पर केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने कानूनी विवादों में उलझी यूनिटेक लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के केंद्र के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी प्रदान दे दी। अदालत ने नए बोर्ड को समाधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए दो महीने का वक्त दिया, साथ ही प्रबंधन को कानूनी कार्यवाही से दो महीने की छूट प्रदान की है। इस बीच कंपनी मामलों के मंत्रालय ने यूनिटेक में करीब 700 करोड़ रुपये के घोटाले को उजागर किया है। उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय ने पाया कि यूनिटेक ने मुखौटा कंपनियों को काफी रकम हस्तांतरित की है। पृष्ठ 2

ललित होटल की प्रवर्तक के परिसरों में आयकर तलाशी

आयकर विभाग ने कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स लिमिटेड समूह के प्रवर्तकों, इसके सहयोगियों और एक प्रमुख वाहन डीलर कंपनी से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी शुरू की है।

भुगतान पर मोहलत की गुहार

दूरसंचार कंपनियों ने एजीआर पर अदालत में दाखिल किया संशोधन आवेदन

सुरजीत दास गुप्ता और मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 20 जनवरी

दूरसंचार ऑपरेटरों ने सर्वोच्च न्यायालय में आज 'संशोधन आवेदन' दायर कर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान की 90 दिन की समयसीमा में बदलाव की मांग की है। इसके साथ ही भुगतान की शर्तों और समय को लेकर दूरसंचार विभाग के साथ बातचीत करने की अनुमति मांगी है।

भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा समूह ने अदालत से इस याचिका को मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने का आग्रह किया क्योंकि 1.47 लाख करोड़ रुपये एजीआर के भुगतान की समयसीमा 24 जनवरी को खत्म हो रही है।

अदालत ने पिछले साल 24 अक्टूबर को दिए आपने आदेश में दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का बकाया 90 दिन के अंदर चुकाने को कहा था। बकाया भुगतान में विफल रहने की स्थिति में अदालत की अवमानना हो सकती है। तीन कंपनियों और समूह के प्रवक्ताओं ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार दूरसंचार विभाग अदालत के आदेश के विरूद्ध कुछ नहीं कर सकता है। इससे पहले दूरसंचार कंपनियों ने संशोधन याचिका लाने की योजना बनाई थी जिसे फिलहाल छोड़ दिया गया था। कंपनियों का मकसद है कि भुगतान के लिए ज्यादा समय मिले और अगर अदालत अनुमति देती है तो वह दूरसंचार विभाग से किस्तों में भुगतान करने पर बात कर सकती हैं, जैसा स्पेक्ट्रम के भुगतान मामले में किया गया था।

स्पेक्ट्रम भुगतान के मामले में दूरसंचार विभाग ने दो साल स्थगन के साथ 16 साल की अवधि में भुगतान तथा स्पेक्ट्रम बैंड के आधार पर 25 से 35 फीसदी अग्रिम भुगतान पर सहमति जताई है। उद्योग की वित्तीय स्थिति, खास तौर पर वोडाफोन आइडिया को देखते हुए सरकार ने हाल ही में अगले वित्त वर्ष से दो अतिरिक्त साल के लिए भुगतान स्थगन की पेशकश की है। इसका अर्थ यह है कि अगले दो वित्त वर्ष में सरकार को अस्थायी तौर पर करीब 50,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

अदालत से राहत नहीं मिलने की स्थिति में उद्योग गंभीर वित्तीय दबाव में फंस सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे में सबसे ज्यादा असर वोडाफोन आइडिया पर पड़ेगा। वैसे, कंपनी पहले ही स्पष्ट करचुकी है कि उसके पास परिचालन बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि इससे रिलायंस जियो पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे एजीआर बकाया के तौर पर केवल 60 करोड़ रुपये चुकाने हैं। सूत्रों का कहना है कि जियो तय समय से पहले ही सारी राशि का भुगतान करने की योजना बना रही है। इस बारे में जानकारी के लिए जियो को ईमेल किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सूत्रों के अनुसार भारती एयरटेल को टेलीनॉर का भी 2,100 करोड़ रुपये का बकाया चुकाना होगा क्योंकि इस कंपनी का विलय किया गया था। लेकिन सौदे में इसका उल्लेख किया गया था कि पिछले बकाये की भरपाई टेलीनॉर द्वारा की जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल और वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला बकाये और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए शनिवार को दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मिले थे।

दूरसंचार कंपनियां इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि अगर उन्हें उच्चतम न्यायालय की तरफ से किस्तों में भुगतान की अनुमति मिलती है तो उनकी रणनीति क्या होगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एजीआर बकाये पर सरकार और कंपनियों के अनुमान

	वोडाफोन आइडिया	भारती एयरटेल
लाइसेंस शुल्क पर सरकार का अनुमान	28,309	21,682
लाइसेंस शुल्क पर कंपनियों का अनुमान	27,610	22,625
स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर सरकार का अनुमान	24,729	12,904
स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर कंपनियों का अनुमान	16,540	11,635

नोट : आंकड़े करोड़ रुपये में स्रोत : सरकार, कंपनी और जेफ्रिज

समाधान पेशेवर पर पंचाट के आदेश पर लगाई रोक

देव चटर्जी
मुंबई, 20 जनवरी

- एनसीएलटी ने पूर्व बैंकरों को समाधान पेशेवर नियुक्त करने पर लगाई थी रोक
- एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी गया था स्टेट बैंक
- पंचाट के फैसले से कई कंपनियों के समाधान पर संकट खड़ा हो गया था

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने पूर्व बैंक अधिकारियों को किसी दिवालिया कंपनी का पेशेवर समाधान नियुक्त करने पर पाबंदी लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) ने हाल में एक आदेश में संभावित पूर्वग्रह के कारण यह पाबंदी लगाई थी।

एनसीएलटी के आदेश से वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और एस्सार प्रोजेक्ट्स सहित कई कंपनियों के कर्ज समाधान पर सवालिया निशान लग गया था क्योंकि कई पूर्व बैंक अधिकारी पहले से ही कर्ज समाधान पेशेवर के रूप में काम कर रहे हैं। एनसीएलएटी ने 17 जनवरी को एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि वह 3 फरवरी को फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। अपील पंचाट ने साथ ही सभी सबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। एनसीएलएटी की कार्यवाही के दौरान ऋणदाताओं ने दलील दी कि कोई भी पात्र व्यक्ति सेवानिवृत्त होने के बाद वकील, समाधान पेशेवर आदि के रूप में काम कर सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह पेशे से जुड़ गया है और बैंक का पूर्व कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति को पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं माना जा सकता है। एनसीएलटी ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम मेटनेयर लिमिटेड वाद में 4 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि कंपनी के लिए ऋणदाताओं ने समाधान पेशेवर के रूप में जिस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया था, वह 39 साल से अधिक समय तक भारतीय स्टेट बैंक में काम कर चुका है और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति से पूर्वग्रह होने की आशंका है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य पाना मुश्किल

जनवरी के मध्य तक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 13 फीसदी तक की गिरावट आई है। इससे पहले दिसंबर में इसमें करीब 4 फीसदी की कमी आई थी। कर अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक दशक में ऐसा कम ही देखने को मिला है। देश के कुल प्रत्यक्ष कर राजस्व में मुंबई का योगदान 37 फीसदी है।

सूत्रों का कहना है कि कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9 लाख करोड़ रुपये भी नहीं पहुंचा है जो 2019-20 के बजट लक्ष्य से करीब 5 लाख करोड़ रुपये कम है। एक कर अधिकारी ने कहा कि अगर यही रुझान रहा तो मौजूदा वित्त वर्ष में 13 लाख करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान को हासिल करना मुश्किल होगा। पृष्ठ 4

आईटीआई का एफपीओ 24 को

सार्वजनिक क्षेत्र की आईटीआई लिमिटेड का 1,600 करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) शुक्रवार को खुलेगा। एफपीओ के तहत 18 करोड़ तक नए शेयर जारी किए जाएंगे। निर्गम 24 जनवरी को खुलेगा और 28 जनवरी को बंद होगा।

व्यापार गोष्ठी

आपकी राय में कैसा हो आम बजट?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

**बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस,
4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com
पर भी भेज सकते हैं**

आज का सवाल

क्या अदालत से दूरसंचार फर्मों को मिलेगी मोहलत

www.bshindi.com
पर राय भेजें।

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या संपत्तियों की बिक्री से पूरा होगा विनिवेश का लक्ष्य?

हां	30.77%
नहीं	69.23%

खबरों में रहे स्टॉक

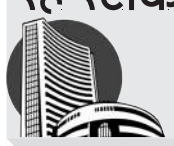

प्रेस्टिज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स

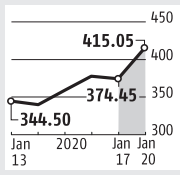

लोखंडवाला डीबी रियल्टी में 50 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण

₹ 374.45 पिछला बंद भाव
₹ 415.05 आज का बंद भाव
▲ 10.84 %

रिलायंस इंडस्ट्रीज

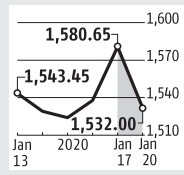

रिफाइनिंग एवं पेट्रोरसायन के लिए कमजोर परिदृश्य जारी रहने के आसार

₹ 1,580.65 पिछला बंद भाव
₹ 1,532.00 आज का बंद भाव
▼ 3.08 %

ल्यूपिन

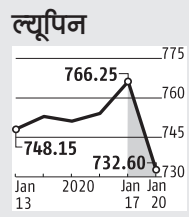

आंध्र प्रदेश के विजाग संयंत्र में यूएसएफडीए की पांच आपत्तियां

₹ 766.25 पिछला बंद भाव
₹ 732.60 आज का बंद भाव
▼ 4.39 %

एनएमडीसी

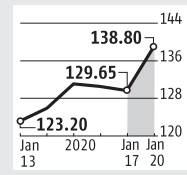

महीने में दूसरी बार लौह अयस्क के दाम बढ़ाए

₹ 129.65 पिछला बंद भाव
₹ 138.80 आज का बंद भाव
▲ 7.06 %

जीएनए ऐक्सल्स

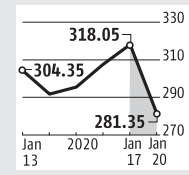

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 63 फीसदी घटा

₹ 318.05 पिछला बंद भाव
₹ 281.35 आज का बंद भाव
▼ 6.52 %

संक्षेप में

आइकिया का ऑनलाइन स्टोर पुणे में खुला

होम फर्निशिंग खुदरा कंपनी आइकिया ने सोमवार को पुणे में अपना नया ऑनलाइन स्टोर खोला। वह मुंबई के बाद उसका दूसरा बाजार है जहां फिजिकल स्टोर से पहले ई-स्टोर को लॉन्च किया गया है। पिछले साल अगस्त में आइकिया ने मुंबई में अपने ई-स्टोर को यह कहते हुए लॉन्च किया था कि वह बाजार में सभी मॉडल का परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब आइकिया ने कहा है कि उसका उद्देश्य अपने सस्ते, सरल और टिकाऊ होम फर्निशिंग समाधान के साथ अधिक से अधिक भारतीय ग्राहकों तक पहुंचना है। *बीएस*

समय डॉट एआई में सिकोया का निवेश

म्यू सिग्मा के पूर्व शीर्ष अधिकारियों- शैली सिंह, दीपेंदर धींगड़ा और पवन पलेटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंटरप्राइज राजस्व वृद्धि कंपनी समय डॉट एआई को लॉन्च करने के लिए साथ आए हैं। यह कंपनी उपभोक्ता पैकेटबंद वस्तु उद्योग पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी ने शुरुआती वित्त पोषण के तहत वेंचर कैपिटल सिकोया इंडिया और सलाहकारों एवं अन्य प्रमुख निवेशकों से 60 लाख डॉलर जुटाए हैं। वैश्विक उपभोक्ता पैकेटबंद वस्तु उद्योग को कारोबार में विस्तार, जटिलताओं और मांग-आपूर्ति परिचालन बेहतर तालमेल न होने के कारण सालाना 8 से 10 फीसदी का नुकसान होता है। *बीएस*

यूनिटेक में रकम की हेराफेरी

रियल एस्टेट कंपनी में करीब 700 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ उजागर

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 20 जनवरी

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक में करीब 700 करोड़ रुपये के घोटाले को उजागर किया है। उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय ने पाया कि यूनिटेक ने विभिन्न मुखौटा कंपनियों को काफी रकम हस्तांतरित की है। एक सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी मामलों के मंत्रालय फिलहाल मामले की जांच कर रहा है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा मकान खरीदारों की रकम हड़पने के आरोप में अगस्त 2017 से ही नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं। दोनों चंद्रा बंधुओं को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया था। उन पर कंपनी की ग्रेटर नोएडा रिहायशी परियोजना में फ्लैट बुक कराने वालों को ठगने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद मामले की जांच का आदेश दिया गया। यूनिटेक मामले की जांच से पता चलता है कि वह रकम 15 से 16 मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित की गई थी।

मंत्रालय की जांच से हुआ खुलासा

- यूनिटेक मामले की जांच से पता चलता है कि वह रकम 15 से 16 मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित की गई थी
- मंत्रालय फिलहाल मामले की जांच कर रहा है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा

सबूतों के साथ जांच के निष्कर्ष सरकार को सौंप दिए गए हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'यूनिटेक के प्रवर्तकों ने इस मुख्य कंपनी से रकम लेकर विभिन्न मुखौटा कंपनियों के तहत भवन और भूमि बैंक जैसी परिसंपत्तियां तैयार की। जबकि वह आम लोगों की रकम थी जिसका संबंध शेयरधारकों और बैंकों से था।'

कंपनी अधिनियम की धारा 224 के तहत कंपनी मामलों के मंत्रालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह जांचकर्ता की रिपोर्ट के आधार कार्रवाई कर सकता है। हाल में मंत्रालय ने इस संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी के प्रबंधन के अधिग्रहण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रस्ताव दिया है। सरकार ने अपने प्रस्ताव में यूनिटेक के निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम भी प्रस्तावित किए हैं जो कभी देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हुआ करती थी।

देश के शीर्ष धनाढ्य लोगों की बिजनेस स्टैंडर्ड की वार्षिक सूची- द बिलियनायर क्लब- में 2007 में चंद्रा परिवार यानी पिता रमेश चंद्रा और बेटे अजय एवं संजय को सातवें पायदान पर रखा गया था। उस समय उनकी शुद्ध हैसियत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी।

वर्ष 2005 से 2007 के बीच रियल एस्टेट क्षेत्र में जबरदस्त तेजी पर सवार यूनिटेक ने अपने कारोबार का तेजी से विस्तार किया और उसने देश भर में कई परियोजनाएं शुरू की थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के प्रवर्तकों को जमानत देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने 30 अक्टूबर 2017 के आदेश के अनुरूप 750 करोड़ रुपये जमा कराने में असफल रहे। इससे पहले दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के बहीखाते और परिसंपत्तियों की फोरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दिया था।

फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि यूनिटेक ने 29,800 मकान खरीदारों से 14,270 करोड़ रुपये जुटाए थे जिसमें से 13,364 करोड़ रुपये का पता बैंक विवरण से चला।

भुगतान पर मोहलत के लिए अदालत से गुहार

पृष्ठ 1 का शेष...

दूरसंचार विभाग की संस्था सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने दस साल तक किस्तों में भुगतान का सुझाव दिया था जिसमें से दो साल छूट के होंगे। लेकिन यह सुझाव इस धारणा पर आधारित था कि कंपनियां ब्याज या जुर्माने के बिना बकाये का भुगतान करेंगी। कंपनियों की दलील है कि सरकार ने लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में 17,500 करोड़ रुपये कमाए हैं।

सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा, 'हम उस राशि पर सवाल नहीं उठा रहे हैं जिसका भुगतान हम कर चुके हैं। अहम सवाल यह है कि हमारे किस्तों में भुगतान का तरीका क्या होगा क्योंकि अधिकांश कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हैं जिनमें शेयरधारक हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह एक व्यावहारिक कारोबार होगा।' मैथ्यू ने कहा कि कंपनियां उस मॉडल पर चर्चा कर रही हैं ताकि उन्हें हर साल एजीआर बकाये के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ न झेलना पड़े। उन्होंने कहा, हम लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कमी का अनुरोध करेंगे जो एजीआर का 13 फीसदी है। हम सरकार से अपील करेंगे कि वह इस राशि में कमी करे ताकि इससे एजीआर बकाये से पड़ने वाले बोझ को खत्म किया जा सके। साथ ही ज्यादा टैरिफ और राजस्व से लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की कुल राशि में बढ़ोतरी होगी।' जो चार कंपनियां उच्चतम न्यायालय में अपील कर रही हैं, उन पर दूरसंचार विभाग का कुल 105,228 करोड़ रुपये बकाया हैं। विभाग के आकलन के मुताबिक वोडाफोन इंडिया को 53,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं। अगर इन कंपनियों को इस वित्त वर्ष के दौरान 10 फीसदी अग्रिम भुगतान का भुगतान करना पड़ता है तो यह राशि 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगी। अगर सभी कंपनियों से 10 फीसदी अग्रिम राशि वसूली जाती है तो यह करीब 14 हजार करोड़ रुपये होगी। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि अगर सरकार स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस फीस में आधी कटौती करती है तो इन कंपनियों को सालाना 8500 करोड़ रुपये की बचत होगी। टाटा समूह का अभी कोई दूरसंचार कारोबार नहीं है।

आकाश एजुकेशन की नजर एडटेक स्टार्टअप पर

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 20 जनवरी

प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली फर्म आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) ने इस महीने के आरंभ में एडटेक फर्म मेरिटनेशन में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद इस क्षेत्र के कई अन्य स्टार्टअप में निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। इससे कंपनी को डिजिटल लर्निंग क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ब्लैकस्टोन के निवेश वाली इस कंपनी ने करीब 80 लोगों की टीम भी तैयार की है। इस टीम के अधिकतर सदस्य स्टार्टअप जगत से हैं जो डिजिटल कारोबार को रफ्तार देने के लिए मेरिटनेशन के अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद टीम से जुड़ेंगे। एईएसएल के निदेशक एवं सीईओ आकाश चौधरी ने कहा, 'हम उन कंपनियों को तलाश रहे हैं जो परीक्षाओं की तैयारी की हमारी प्रमुख ताकत अथवा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हों।'

'मुकदमेबाजी से छवि धूमिल'

देव चटर्जी
मुंबई, 20 जनवरी

पिछले एक साल से मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट (मायल) में अपनी 13.5 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री का इंतजार कर रहे दक्षिण अफ्रीका के बिडवेस्ट ग्रुप ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि जीवीके ग्रुप की लंबी और अफसोसनाक मुकदमेबाजी से कंपनी को नुकसान हुआ है। पत्र में कहा गया है कि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत की छवि धूमिल हुई है।

बिडवेस्ट ने 17 जनवरी को लिखे पत्र में कहा है, 'इसने न केवल हमें नुकसान पहुंचाया है बल्कि इससे विदेशी निवेश के अनुकूल जगह के तौर पर भारत भी छवि भी खराब हुई है।' पिछले साल मार्च में बिडवेस्ट ने 1,250 करोड़ रुपये में अपनी पूरी हिस्सेदारी अदाणी समूह को बेचने का निर्णय लिया था और ठीक उसी समय मायल के अन्य हिस्सेदारों को भी उसने अपनी हिस्सेदारी बिक्री की पेशकश की थी। यह पेशकश मायल के शेयरधारकों के बीच हस्ताक्षरित पहले इनकार करने के अधिकार के तहत की गई थी।

मायल में जीवीके ग्रुप की 50.5 फीसदी हिस्सेदारी है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हिस्सेदारी 28 फीसदी है। जबकि शेष हिस्सेदारी बिडवेस्ट और एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका (एसीएसए) के पास है। जीवीके ग्रुप ने बिडवेस्ट की हिस्सेदारी खरीदने के लिए राजी था लेकिन वह अप्रैल 2019 में 30 दिनों के भीतर रकम का इंतजाम करने में विफल रहा। उसके बाद जीवीके ग्रुप ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया ताकि अदाणी ग्रुप के साथ होने जा रहे सौदे को रोका जा सके। लेकिन पिछले साल जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीवीके की याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पीठ ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के जरिये इस मुद्दे को निपटाने के लिए कहा था।

बिडवेस्ट ने नागर विमानन मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है, 'जीवीके का उद्देश्य हमारी बिक्री प्रक्रिया को ठप करना है।' उसने कहा है कि कुल मिलाकर बेवजह मुकदमेबाजी में मायल प्रबंधन का समय बर्बाद हुआ जबकि भारत में उसकी पहली प्राथमिकता नवी मुंबई में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास है। बिडवेस्ट में इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग की है। पिछले साल सितंबर में मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने बिडवेस्ट को अपने शेयर अदाणी ग्रुप को बेचने पर रोक लगा दिया था।

समाधान पेशेवर पर पंचाट के आदेश पर लगाई रोक

पृष्ठ 1 का शेष...

पंचाट का कहना था कि इस तरह के समाधान पेशेवर के निष्पक्ष तरीके से काम करने की संभावना नहीं है और उनके एक स्वतंत्र अंपायर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पंचाट ने कहा कि वित्तीय लेनदारों को समाधान पेशेवर के रूप में कोई नया नाम सुझाना चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीएलटी के आदेश का व्यापक असर होता और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज तथा एस्सार प्रोजेक्ट्स जैसी बड़ी कंपनियों के ऋण समाधान की प्रक्रिया सुस्त पड़ जाती। वीडियोकॉन इंडस्टीज पर बैंकों का 40 हजार करोड़ रुपये और एस्सार प्रोजेक्ट्स पर 7,700 करोड़ रुपये का बकाया है। एक कॉरपोरेट वकील ने कहा, 'एनसीएलटी के आदेश से उन कई खातों पर सवालिया निशान लगा जाता जहां समाधान पेशेवर की नियुक्ति हो चुकी है और समाधान की प्रक्रिया अग्रिम चरण में पहुंच चुकी है।'

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पहले ही चार ऋण समाधान पेशेवर नियुक्त कर चुकी है जिनमें प्राइस वाटरकूपरहाउस और केपीएमजी शामिल हैं। अब डेलॉयट उसकी परिसंपत्ति बिक्री का प्रबंधन कर रही है। कंपनी के ऋण समाधान की प्रक्रिया जनवरी 2018 से चल रही है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण समाधान के लिए भेजी गई 29 कंपनियों की अपनी दूसरी सूची में वीडियोकॉन को शामिल किया था।

आर्सेलर-निप्पॉन की नजर हजीरा जेटी पर

विनय उमरजी और ईशिता आयान दत्त
अहमदाबाद/कोलकाता, 20 जनवरी

आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील का संयुक्त उद्यम एएम/एनएस गुजरात के हजीरा में एस्सार समूह के रुइया परिवार से निजी जेटी का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एएम/एनएस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया लेकिन राज्य सरकार के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कंपनी ने एस्सार बल्क टर्मिनल (ईबीटीएल) से लाइसेंस हस्तांतरित करने के लिए आवेदन किया था। ईबीटीएल में एस्सार की बहुलांश हिस्सेदारी है।

एएम/एनएस इस पहल के साथ दलील दी है कि उसके इस्पात संयंत्र के लिए यह एक निजी लाइसेंस है और निजी जेटी संयंत्र के पास बरकरार रहना चाहिए। रुइया परिवार के साथ लंबे संघर्ष के बाद दिवालिया कानून के तहत आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील ने पिछले महीने संयुक्त रूप से एएम/एनएस इंडिया (पूर्व में एस्सार स्टील इंडिया यानी ईएसआईएल) का अधिग्रहण किया था। हालांकि उस सौदे में ईएसआईएल की परिसंपत्तियों में स्लरी पाइपलाइन, बिजली संयंत्र एवं बंदरगाह प्रतिष्ठान जैसी कुछ सहायक इकाइयों को शामिल नहीं किया गया था।

राज्य की नीति

हालिया घटनाक्रम की मुख्य वजह गुजरात मैरिटाइम बोर्ड की नीति में बदलाव है। अक्टूबर में उसने एक नई नीति की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य मौजूदा निजी जेटीधारकों को तीसरे पक्ष के कार्गो की हैंडलिंग की अनुमति देना था।

करीब दो दशक पहले जीएमबी ने एक नामांकन के आधार पर निजी कंपनियों को निजी जेटी के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी ताकि आयात-निर्यात संबंधी उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

गुजरात तट पर उसके 38 जेटी में 8 से 15 करोड़ टन सालाना क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। नई नीति का उद्देश्य उन सभी 38 निजी जेटी के लिए कारोबार के तरीके को आसान बनाना है ताकि वाणिज्यिक कार्गो के हैंडलिंग के लिए अलग-अलग मंजूरी की जरूरत नहीं हो। इसके तहत मौजूदा निजी जेटीधारकों को इसे अपनाने या न अपनाने का विकल्प दिया गया है। ईबीटीएल ने इस नीति को अपनाया और इसलिए उसे जीएमबी के साथ पूरक अनुबंध करने की जरूरत हुई। जबकि आर्सेलरमित्तल उसका विरोध कर रही है।

मॉरीशस से घट रहा एफपीआई निवेश

इस इलाके में पंजीकृत विदेशी फंडों का 5 फीसदी से भी कम भारत में कर रहा है निवेश

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 20 जनवरी

पिछले साल मॉरीशस से भारत में होने वाला विदेशी निवेश घट गया क्योंकि निवेशकों ने अपने गृह प्रदेश अमेरिका और अन्य इलाकों आयरलैंड और लक्जमबर्ग में निवेश किया और इस तरह से भारत में होने वाले निवेश में कटौती की।

मॉरीशस में पंजीकृत फंडों के नए निवेश में कमी आई और साल 2019 की शुरुआत से इस क्षेत्र से नए विदेशी फंडों का महज 4.3 फीसदी ही इस देश में आया। इसकी तुलना में अमेरिका में 32 फीसदी और लक्जमबर्ग और आयरलैंड में कुल मिलाकर 24 फीसदी निवेश हुआ। साल 2015 में मॉरीशस से नया पंजीकरण 8.4 फीसदी था।

मॉरीशस से औसत मासिक परिसंपत्ति साल 2019 में एक साल पहले के मुकाबले 10 फीसदी घटकर 4.33 लाख करोड़ रुपये रह गया और इक्विटी निवेश 10 फीसदी घटकर 3.97 लाख करोड़ रुपये रहा। एनएसडीएल के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर डी. सिंह ने कहा, सिर्फ संधि का फायदा लेने के लिए मॉरीशस का इस्तेमाल निवेश के लिए करने वाले निवेशक संधि`में संशोधन और भारतीय आयकर अधिनियम के तहत गार के नियम लागू किए जाने के ब ाद निश्चित तौर पर सावधान हो गए हैं क्योंकि वास्तव में मॉरीशस के जरिए निवेश का कोई फायदा नहीं रह गया है।

भारत ने साल 2016 में मॉरीशस के साथ कर संधि में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के आधार पर 1 अप्रैल 2017 से पहले अधिग्रहीत भारतीय इक्विटी की ग्रैंडफादरिंग की गई और पूंजीगत लाभ कर से छूट दी गई। इस अवधि के बाद खरीदे गए और 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए शेयरों पर 50 फीसदी रियायती कर का भुगतान करना पड़ा। संक्रमण के इस चरण में मॉरीशस से लॉन्ग इक्विटी फंडों का परिचालन जारी रहा क्योंकि ग्रैंडफादरिंग का उपबंध लागू था। चूंकि संक्रमण की अवधि पूरी हो गई है, लिहाजा अब इक्विटी फंडों के लिए इन देशों से परिचालन का कोई फायदा नहीं रह गया।

1 अप्रैल 2019 या उसके बाद इक्विटी निवेश के मामले में एक साल से ज्यादा वाले निवेश पर कर की दर 10 फीसदी और एक साल से नीचे वाले निवेश पर 15 फीसदी है।

विल्सन फाइनैंशियल सर्विसेज की निदेशक नेहा कुलकर्णी का मानना है कि करेंसी व स्टॉक डेरिवेटिव में लेनदेन के इच्छुक निवेशक अब मॉरीशस पर दोबारा विचार करेंगे क्योंकि एफपीआई की श्रेणी-2 के लिए ऐसी योजनाओं पर निवेश की सीमा घटा दी गई है।

एफपीआई के लिए हालिया नियामकीय दिशानिर्देश में मॉरीशस के दो तिहाई से ज्यादा फंडों को दूसरी श्रेणी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। कुलकर्णी ने कहा, कैटिगरी-2 एफपीआई के लिए स्टॉक व इंडेक्स डेरिवेटिव में पोजीशन की सीमा कैटिगरी-1 एफपीआई के मुकाबले काफी ज्यादा घटा दी गई है। कैटिगरी-2 एफपीआई मसलन कॉरपोरेट निकाय, व्यक्ति या फैमिली ऑफिस के ट्रेड के लिए अग्रिम मार्जिन और नया केवाईसी जरूरी है।

कुलकर्णी ने कहा, जब तक मॉरीशस एफएटीएफ का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनता उसके लिए ज्यादातर एफपीआई को बनाए रखना काफी मुश्किल होगा।

सिंह ने कहा, कनेक्टिविटी व बड़े वर्कफोर्स की उपलब्धता के कारण सिंगापुर में कामकाज की स्थापना आसान हो सकती है। अगर सिंगापुर के नए वैरिएबल कैपिटल कंपनी की व्यवस्था कामयाबी के साथ लागू होती है तो यह भारत केंद्रित हेज फंड व क्रेडिट फंड की स्थापना आसान बना देगा।

एशियाई निवेशकों के लिए मॉरीशस तरजीही गंतव्य बना हुआ है, खास तौर से जो डेट व डेरिवेटिव में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि इन परिसंपत्ति वर्गों में निवेश पर कोई कर नहीं देना होता है और ऋण प्रतिभूतियों के ब्याज पर ही कर लगता है। एफपीआई परिसंपत्ति के लिहाज से यह अभी भी दूसरे नंबर पर है यानी लक्जमबर्ग, सिंगापुर और ब्रिटेन से आगे।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

- इसकी तुलना में अमेरिका में 32 फीसदी और लक्जमबर्ग और आयरलैंड में कुल मिलाकर 24 फीसदी निवेश हुआ। साल 2015 में मॉरीशस से नया पंजीकरण 8.4 फीसदी था
- मॉरीशस में पंजीकृत फंडों के नए निवेश में कमी आई और साल 2019 की शुरुआत से इस क्षेत्र से नए विदेशी फंडों का महज 4.3 फीसदी ही इस देश में आया
- मॉरीशस से औसत मासिक परिसंपत्ति साल 2019 में एक साल पहले के मुकाबले 10 फीसदी घटकर 4.33 लाख करोड़ रुपये रह गया
- इस अवधि में इक्विटी निवेश 10 फीसदी घटकर 3.97 लाख करोड़ रुपये रहा

गिफ्ट सिटी में रुपया-डॉलर डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति

राजेश भयानी
मुंबई, 20 जनवरी

इंटरनैशनल फाइनैंशियल सेंटर (गिफ्ट सिटी) गांधीनगर, गुजरात में बीएसई व एनएसई की तरफ से स्थापित स्टॉक एक्सचेंज में जल्द ही रुपया-डॉलर डेरिवेटिव कारोबार शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये वाले डेरिवेटिव कारोबार इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर में करने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार रात सरकार ने एक अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा में संशोधन किया गया है ताकि गिफ्ट सिटी में स्थापित एक्सचेंजों में रुपये में डेरिवेटिव में कारोबार शुरू किया जा सके।

आरबीआई ने रुपया एक्सचेंज रेट फ्यूचर ऐंड ऑप्शंस की अनुमति दी है और इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक, रुपये को शामिल करते हुए किसी दो मुद्रा में करेंसी डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति आईएफएससी में स्थापित स्टॉक एक्सचेंजों में करने की अनुमति दी गई है। रुपये वाले अनुबंध का निपटान भारतीय रुपये के बजाय अन्य मुद्रा में होगा और प्रवासी भारतीय ये डेरिवेटिव अनुबंध ले सकते हैं।

इस सुविधा का मकसद विदेश के रुपया बाजार को भारत लाना है। अभी रुपये का कारोबार विदेशी एनडीएफ यानी बिना डिलिवरी वाले फॉरवर्ड में होता है। पिछले साल अक्टूबर में आरबीआई न कहा था कि उषा थोराट की अगुआई वाले टास्क फोर्स की दो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है और उनमें से एक है गिफ्फ्ट सिटी में रुपया एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति देना।

टास्क फोर्स ने देसी बैंकों को हर समय प्रवासी को विदेशी विनिमय की कीमत की पेशकश की अनुमति देने की भी सिफारिश की थी। यह या तो देसी बिक्री टीम के जरिए हो सकता है या फिर उनकी विदेशी शाखाओं के जरिये।

अभी क्रॉस-करेंसी ट्रेड की अनुमति गिफ्ट सिटी में बीएसई व एनएसई के इंटरनैशनल एक्सचेंज में है। हालांकि इसका कारोबार काफी कम है क्योंकि रुपये में कारोबार नहीं होता है।

साल 2018 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रुपये में 23 अरब डॉलर का कारोबार किया, वहीं आरबीआई के सूत्रों का अनुमान है कि साल 2019 के लिए डिलिवरी वाले रोजाना देसी फॉरवर्ड 21 अरब डॉलर का होगा। इसका मतलब यह है कि रुपये का विदेशी बाजार देसी बाजार के मुकाबले बड़ा बन गया है।

उषा थोराट की अगुआई में गठित आरबीआई के टास्क फोर्स ने गिफ्ट सिटी में रुपये में डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति देने की सिफारिश की थी। आरबीआई ने हालांकि इस पर ऐतराज जताया था क्योंकि देसी बाजार पर इसके असर की संभावना थी। हालांकि यह असर तब भी पड़ता है जब विदेशी बाजार में भारी हलचल होती है।

गिफ्ट सिटी में एक्सचेंजों का परिचालन 22 घंटे होता है, ऐसे में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को एनडीएफ पर हेजिंग की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त वक्त मिल सकता है, लेकिन आरबीआई की मंजूरी के बाद ही यह हो पाएगा।

भारतीय एक्सचेंजों में करेंसी डेरिवेटिव में प्रवासी इकाइयों की भागीदारी को आरबीआई को प्रतिबंधित करता है और यह उनके अंतर्निहित निवेश की सीमा तक है। नियामकीय प्राधिकरण के प्रभाव से बाहर व्यापक बाजार उनके प्रभाव को कमजोर बनाता है। गिफ्ट आईएफएससी एक्सचेंजों में डेरिवेटिव की सभी योजनाओं की अनुमति है और अपवाद के तौर पर रुपया डेरिवेटिव का कारोबार नहीं होता है।

बीआईएस के आंकड़ों के मुताबिक, छह मुद्राओं कोरियाई वॉन, भारतीय रुपये, चीन की रेनमिबिनी, ब्राजील की रियाल, ताइवान के डॉलर और रूस के रूबल में होने वाला एनडीएफ वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल एनडीएफ कारोबार में करीब दो तिहाई की हिस्सेदारी रखता है।

बीएस बातचीत

खनन टाटा स्टील के लिए भविष्य में वृद्धि का नया क्षेत्र

इस्पात उद्योग का मुनाफा वर्ष 2019-20 में इससे पिछले साल की तुलना में प्रभावित हो रहा है। टाटा स्टील के कार्यकारी निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी **कौशिक चटर्जी** ने **ईशिता आयान दत्त** को बताया कि 2020-21 में संभावनाएं अच्छी हैं क्योंकि अगले छह महीनों में मांग तगड़ी रहने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील ने अगले दशक में भारत में अपनी वृद्धि के लिए खाका तैयार किया है। बातचीत के अंश :

ब्रेक्जिट से टाटा स्टील यूरोप कैसे प्रभावित होगी?
हम कुछ वर्षों से लगातार स्थिति का आकलन कर रह हैं। हमने इस बदलाव से निपटने के लिए आपूर्ति शृंखला और ग्राहक सेवा जरूरतों समेत आपात योजना बनाई है। हमारी उन विशेष कारोबारी समझौतों पर भी नजर रहेगी, जो ब्रिटेन-यूरोपीय संघ के बीच होंगे।

क्या परिसंपत्तियों की बिक्री, क्षमता घटाने और नौकरियों में कटौती से टाटा स्टील यूरोप की हालत सुधरेगी?
हमने सभी चक्रों में कारोबार से धन की आवक को सकारात्मक और सतत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सुधार कार्यक्रम बनाया गया है। यूरोप जैसे क्षेत्रों में लागत घटाने के कार्यक्रम बहुत अहम हैं।

क्या यूरोप के सुधार कार्यक्रम में पहले से घोषित 3,000 से अधिक छंटनी भी शामिल हैं?
सुधार कार्यक्रम के कई हिस्से हैं और उनमें से एक उत्पादकता है। हमारा जोर विभिन्न उपायों के जरिये लागत को घटाना है। यूरोप की अगुआ टीम के हमारे साथी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि विभिन्न पहलों के जरिये लागत घटाने के तरीके खोजे जा सकें।

कलिंगनगर में दूसरे चरण के बाद घरेलू बाजार में विस्तार की क्या योजनाएं हैं?
हमने भारत में अगले एक दशक में वृद्धि के लिए व्यापक खाका तैयार किया है, जिसमें जमशेदपुर, कलिंगनगर और अंगुल समेत हमारी सभी प्रमुख साइट शामिल हैं। हमारे आकलन में व्यापक उत्पाद और तकनीक शामिल हैं, इसलिए हम भविष्य में वृद्धि के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्या टिनप्लेट, टाटा स्टील डिस्ट्रीब्यूशन और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का विलय करने की योजना है?
इस्पात के लंबे उत्पादों के कारोबार के विलय की कोई योजना नहीं है। टिनप्लेट और टाटा स्टील डिस्ट्रीब्यूशन टाटा स्टील के डाउनस्ट्रीम पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और पोर्टफोलियो को आसान बनाने की प्रक्रिया के तहत डाउनस्ट्रीम क्लस्टर का हिस्सा होंगी। ये दोनों टाटा स्टील की सहायक हैं और हम पूरे क्लस्टर की प्रबंधन प्रक्रिया को बेहतर करने पर काम कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में घरेलू मांग को लेकर क्या परिदृश्य है?
मेरा मानना है कि अगले छह महीने अच्छे रहेंगे और हमेशा ऐसा होता भी रहा है क्योंकि दुनियाभर में इस उद्योग के लिए जनवरी से जून की अवधि सबसे बेहतर होती है। अच्छी बात यह कि इस पूरी मूल्य शृंखला में स्टॉक कम है। इसलिए फिर से स्टॉक करने की मांग आनी शुरू हो गई है। हमारा अनुमान है कि ज्यादातर क्षेत्रों में मांग और कीमतों में मजबूती आएगी।

कारोबारी खनन को लेकर क्या योजनाएं हैं?
एक सदी से अधिक समय से खनन कर रही किसी कंपनी के लिए यह स्वाभाविक रणनीतिक प्रगति है। हम चुनिंदा खनिजों में अपना खनन पोर्टफोलियो विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत में खनन क्षेत्र खोले जाने पर हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे। अब हमारे पास ऐसी कंपनी है, जो व्यावसायिक खनन के लिए प्रतिबद्ध है और पोर्टफोलियो और क्षमता में इजाफा करेगी। यह टाटा स्टील के लिए भविष्य में वृद्धि का नया क्षेत्र है।

वित्त मंत्री के लिए मंदी का कोई समाधान?
इस बार भारत वैश्विक मंदी से अछूता नहीं रह पाया है। इसकी वजह कई आंतरिक कारक हैं, इसलिए सुधार धीमा रहेगा और इसके लिए कई स्तरों पर उपाय करने होंगे।

सीपीएसई में फेरबदल से पीएसयू शेयरों में उठापटक

सूचकांक में शामिल कंपनियों में बड़े निवेशकों का निवेश संभव

बीएस संवाददाता
मुंबई, 20 जनवरी

निफ्टी सीपीएसई सूचकांक कुछ शेयरों को शामिल और कुछ को बाहर किए जाने के बाद सोमवार को सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भारी उठापटक देखने को मिली। निफ्टी सीपीएसई सूचकांक उस सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लिए पोर्टफोलियो का काम करता है, जिसका इस्तेमाल सरकार पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए करती है। इंडियन ऑयल (आईओसीएल) के शेयर की कीमत 4.2 फीसदी गिरकर बंद हुई, जबकि पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) की कीमत 7.9 फीसदी लुढ़क गई।

आईओसीएल और पीएफसी को 24 जनवरी से सूचकांक से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि कोचीन शिपयार्ड, एनएचपीसी, एनएमडीसी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सूचकांक में शामिल किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड के शेयर की कीमत 3.5 फीसदी चढ़कर बंद हुई। वहीं जलविद्युत क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी का शेयर 11.8 फीसदी, एनएमडीसी का 7.1 फीसदी और पावर ग्रिड का शेयर 3.7 फीसदी चढ़े।

> आईओसीएल और पीएफसी को सूचकांक से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि कोचीन शिपयार्ड, एनएचपीसी, एनएमडीसी और पावर ग्रिड को शामिल किया जाएगा

एडलवाइस में अनुसंधान प्रमुख विनय खट्टर ने कहा, 'इन कंपनियों के शेयरों में तेजी इसलिए आई है क्योंकि अब ईटीएफ का हिस्सा बनने के बाद उनमें बड़े संस्थागत निवेशकों के निवेश करने की संभावना है। अयस्क की कीमतों में तेजी के कारण एनएमडीसी जैसी कंपनी के शेयर चढ़े हैं।'

सीपीएसई सूचकांक के लिए पात्रता के मानदंडों में भी बदलाव किया गया है। पहले जिन शेयरों में सरकार की हिस्सेदारी 51.5 फीसदी से अधिक थी, वे सीपीएसई ईटीएफ में शामिल होने के हकदार होते थे। नए मानदंडों में कहा गया है कि जिन शेयरों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी होगी, वे सीपीएसई सूचकांक में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। चालू वित्त वर्ष में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एयर इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों में रणनीतिक बिक्री के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में निवेश बैंकरों का कहना है कि सरकार सीपीएसई-ईटीएफ की अगली खेप के जरिये फरवरी में करीब 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

निवेश बैंकरों का कहना है कि सरकार ने उन शेयरों को शामिल किया है, जिनमें उसकी हिस्सेदारी 50 फीसदी के आंकड़े से काफी अधिक है। एक निवेश बैंकर ने कहा, 'एनएमडीसी, एनएचपीसी और कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 70 फीसदी से अधिक है।'

कोटक महिंद्रा बैंक का एकीकृत कर-पूर्व लाभ 6.3 फीसदी बढ़ा

अनूप रॉय
मुंबई, 20 जनवरी

कोटक महिंद्रा बैंक का एकीकृत कर पूर्व लाभ दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही में 6.26 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,889.47 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,719.30 करोड़ रुपये रहा था। पेंशन से संबंधित एकमुश्त 200 करोड़ रुपये का खर्च और उच्च प्रावधान के कारण लाभ पर असर पड़ा। बैंक का शुद्ध लाभ 27.4 फीसदी बढ़कर तीसरी तिमाही में 2,348.72 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,844.01 करोड़ रुपये रहा था।

एकल आधार पर बैंक का कर पूर्व लाभ 1,944 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 1.35 फीसदी कम है। ऋण में 10 फीसदी की बढ़ोतरी पिछली तिमाहियों से कम रही। बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता ने कहा, जब अर्थव्यवस्था की नॉमिनल बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है तो ऋण में इजाफा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उधार लेने वाली इकाइयों संख्या कम हुई है।

बैंक ने उधार देने में सतर्कता बरती है। गुप्ता ने कहा, आज उधार देना आसान है, लेकिन इसका असर दो-तीन साल बाद महसूल किया जाएगा। जब हम उधार देते हैं तो हम सिर्फ 2 फीसदी कमाई करते हैं, लेकिन जब हम गंवाते हैं तो कर्ज का पूरा हिस्सा चला जाता है। जब खुदरा में सुरक्षित कर्ज कम हो रहा है तो कोटक महिंद्रा असुरक्षित कर्ज में थोड़ा अवरोध लगा रहा है। एकल आधार पर बैंक की शुद्ध ब्याज आय 17 फीसदी बढ़कर 3,430 करोड़ रुपये रही। वहीं शुद्ध ब्याज मार्जिन एक साल पहले की समान अवधि के 4.31 फीसदी के मुकाबले 4.69 फीसदी पर पहुंच गया। सितंबर तिमाही में यह 4.61 फीसदी रहा था।

बैंक का सकल एनपीए एकल आधार पर तिमाही में बढ़कर 2.46 फीसदी पर पहुंच गया, जो सितंबर तिमाही में 2.32 फीसदी रहा था। एक साल पहले की समान अवधि में यह 2.07 फीसदी रहा था। इस तिमाही में फंसे कर्ज में करीब 1,062 करोड़ रुपये जुड़े, जिसका एक तिहाई कंपनियों के खाते से आया।

बैंक की कुल एकीकृत आय सालाना आधार पर 19.34 फीसदी बढ़कर 13,542.43 करोड़ रुपये रही। पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.2 फीसदी रहा जबकि टियर-1 अनुपात 17.7 फीसदी। आज बैंक का शेयर बीएसई पर 4.7 फीसदी की गिरावट के साथ 1,618 रुपये पर बंद हुआ।

(डिस्क्लेमर : कोटक फैमिली की तरफ से नियंत्रित इकाइयों के पास बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड की अहम हिस्सेदारी है)

अशोक लीलैंड ने दिल्ली में उतारे बीएस-6 ट्रक

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 20 जनवरी

व्यावसायिक वाहन क्षेत्र की कंपनी अशोक लीलैंड ने बीएस-6 पर करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस राशि में से करीब 300 से 350 करोड़ रुपये वह नया प्लेटफॉर्म बनाने पर खर्च हुए हैं, जिसके आधार पर नए वाहन जारी किए जाएंगे।

इस बीच कंपनी के प्रबंधन का अनुमान है कि मध्यम एवं भारी वाहन (एमऐंडएचसीवी) उद्योग की बिक्री इस वित्त वर्ष 2019-20 में करीब दो लाख रहेगी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष से करीब 46.23 फीसदी कम है। कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपने ग्राहकों को बीएस-6 ट्रकों की पहली खेप की डिलिवरी की सोमवार को घोषणा की। अशोक लीलैंड के मुख्य परिचालन अधिकारी अनुज कथुरिया ने कहा कि कंपनी ने बीएस-6 को अपनाने पर करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें 300 से 350 करोड़ रुपये एक नया प्लेटफॉर्म बनाने पर खर्च किए गए हैं।

कंपनी ने नया मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बनाया है। कंपनी ने भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म पर अपने मझोले और भारी वाहन बनाने की योजना बनाई है। इससे हिंदुजा समूह की इस अग्रणी कंपनी को किफायती तरीके से विभिन्न ग्राहकों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।

आंध्र प्रदेश ने पेश किया 3 राजधानियों का प्रस्ताव

बीएस संवाददाता
हैदराबाद, 20 जनवरी

आंध्र प्रदेश सरकार ने आज राज्य विधानसभा में ऐतिहासिक विधेयक पेश किया है। इसमें राज्य में तीन राजधानियां, अमरावती में विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम मे कार्यकारी राजधानी और हैदराबाद में न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले के साथ अमरावती को पूरी तरह से राज्य की नई राजधानी बनाने का पहले की सरकार का प्रस्ताव समय के पहले ठहर गया है। आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन ऐंड इनक्लूसिव डेवलपमेंट आफ आल रीजंस ऐक्ट 2020 नाम से पेश इस विधेयक में सचिवालय, सरकार के विभागों के प्रमुखों के प्रमुखों के कार्यालय व राजभवन विशाखापत्तनम स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, जिसे कार्यकारी राजधानी बनाने का प्रस्ताव है।

मुंबई में कर संग्रह गिरने से बढ़ी चिंता

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 20 जनवरी

- **मुंबई में प्रत्यक्ष कर संग्रह जनवरी के मध्य तक करीब 13 प्रतिशत गिरा**
- **मुंबई का देश के कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है**
- **दिसंबर तक मुंबई में कुल कर संग्रह 2.20 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के 2.30 लाख करोड़ रुपये से 4.3 प्रतिशत कम है**
- **31 दिसंबर को विभाग ने बड़ी मात्रा में रिफंड दिया जिससे आगे 2 अंकों की गिरावट और हो सकती है**

भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में प्रत्यक्ष कर संग्रह जनवरी के मध्य तक करीब 13 प्रतिशत गिरा है। वहीं दिसंबर में कर संग्रह में 4 प्रतिशत की मामूली कमी आई थी। कर अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक दशक में ऐसा बहुत कम हुआ है। इस शहर की देश के कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में हिस्सेदारी 37 प्रतिशत रही है।

सूत्रों ने कहा कि कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9 लाख करोड़ रुपये तक भी नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में तय कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 2 महीने का लक्ष्य बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रहती है तो इससे चालू वित्त वर्ष में 13 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह करने के बजट में तय लक्ष्य पर विपरीत असर पड़ेगा।

कर संग्रह में तेज गिरावट को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर तत्काल बैठक बुलाई है। बोर्ड ने कहा है कि सभी प्रधान मुख्य आयुक्त व उस रैंक के अधिकारी इस बैठक में शामिल हों और अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च) में कर वसूली की उचित रणनीति पर चर्चा करें, जिससे बजट में निर्धारित कर संग्रह का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय भी स्थिति से अवगत है और आगामी 1 फरवरी को प्रस्तावित बजट को देखते हुए प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य की तत्काल समीक्षा करने को कहा है।

दिसंबर तक मुंबई में कुल कर संग्रह 2.20 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 2.30 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह की तुलना में 4.3 प्रतिशत कम है। आईटी के एक अधिकारी ने कहा कि 31 दिसंबर को विभाग ने बड़ी मात्रा में रिफंड दिया है, जिससे आगे 2 अंकों की गिरावट और हो सकती है।

एक और वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह गंभीर चिंता का विषय है और कोई रास्ता नहीं है कि हम बजट में तय लक्ष्य के करीब भी पहुंच सकें।'

बहरहाल माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर निकाय ने अपने फील्ड अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह कवायद तेज करें और कर बकाया और मौजूदा मांग की वसूली पर ध्यान केंद्रित करें। आकलन और जांच टीम के अलावा शीर्ष निकाय ने अंतरराष्ट्रीय कराधान शाखा और आयुक्त (अपील) के अधिकारियों से भी अहम मामलों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है, जिनकी वजह से कर संग्रह के आंकड़ों को बल मिल सकता है।

इसके अलावा आईटी अधिकारियों से कहा गया है कि वे संपत्ति के विक्रेताओं के अग्रिम कर के भुगतान की पुष्टि करें, जिनमें खरीदार ने स्रोत पर कर भुगतान किया है, लेकिन इसका भुगतान सरकार के खाते में नहीं हुआ है।

सीबीडीटी ने कहा है कि अधिकारियों को इलाके और अपने अधिकार क्षेत्र के मुताबिक अन्य रणनीतियां अपनाने की भी जरूरत है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि दूसरी तिमाही(जुलाई से सितंबर) में कर संग्रह पटरी से उतर गया। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ रिकवरी होगी और दिसंबर तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में कुछ सकारात्मक खबर मिलेगी। लेकिन तीसरी तिमाही में अग्रिम कर संग्रह के आंकड़ों ने विभाग के भीतर चिंता पैदा कर दी है।

अग्रिम कॉर्पोरेशन कर संग्रह तीसरी तिमाही में गिरकर 73,000 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 77,000 करोड़ रुपये था। वहीं व्यक्तिगत आयकर का अग्रिम भुगतान बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 19 की समान अवधि में 24,000 करोड़ रुपये था।

15 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.34 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 7.96 करोड़ रुपये था। कर संग्रह, शुद्ध रिफंड करीब 6.75 लाख करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 6.7 लाख करोड़ रुपये था।

भारत ने गिराई वैश्विक आर्थिक वृद्धि : आईएमएफ

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है। यह अनुमान 5 प्रतिशत आधिकारिक अग्रिम वृद्धि अनुमान से कम है।

आईएमएफ का यह अनुमान उसके पहले के अनुमान की तुलना में 1.3 प्रतिशत कम है। मुद्रा कोष ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि कम होने की वजह से विश्व की वृद्धि दर का अनुमान नीचे आएगा। आईएमएफ का वृद्धि दर का नया अनुमान अर्थशास्त्रियों के बयान की पुष्टि करता है, जिनका कहना है कि 2019-20 के अग्रिम अनुमान की गणना बढ़ा चढ़ाकर की गई है।

आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले साल 5.8 प्रतिशत रहेगी, जो उसके पहले के अनुमान की तुलना में 1.2 प्रतिशत कम है। साथ ही एजेंसी ने कहा है कि 2021-22 में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी, जो उसके पहले के अनुमान की तुलना में 0.9 प्रतिशत अंक कम है।

आईएमएफ का अनुमान है कि विश्व की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 1.9 प्रतिशत रहेगी, जो उसके पहले के अनुमान की तुलना में 0.1 प्रतिशत कम है। इसी तरह से चालू कैलेंडर साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पहले के अनुमान की तुलना में 0.1 प्रतिशत कम है। वहीं 2022 के लिए वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पहले के अनुमान की तुलना में 0.2 प्रतिशत कम है।

आईएमएफ ने कहा है, 'वृद्धि दर कम करने की वजह यह है कि खासकर भारत सहित कुछ उभरते बाजारों में आर्थिक गतिविधियां सुस्त रहने का अनुमान है। इसकी वजह से अगले 2 साल की वृद्धि पर भी असर पड़ने की संभावना है।'

आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक बाजार में वृद्धि कम होने की वजह भारत के अनुमान में बदलाव है है, जहां घरेलू मांग उम्मीद से बहुत ज्यादा तेजी से गिरी है और गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों की वजह से कर्ज देने की वृद्धि दर घटी है।

आईएमएफ प्रमुख गीता गोपीनाथ ने अपने ब्लॉग में कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के अनुमान में प्रमुख भूमिका भारत की है, जहां गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में दबाव और कमजोर ग्रामीण आर्थिक वृद्धि के कारण दबाव बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि 2020 की वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर भी बहुत ज्यादा अनिश्चितता है क्योंकि यह अर्जेंटीना, ईरान और तुर्की जैसी दबाव वाली अर्थव्यवस्थाओं और कम प्रदर्शन वाले उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, भारत और मैक्सिको पर निर्भर होगा।

शराब पर रोक से महंगे होंगे हवाई टिकट

अनीश फडणीस और अरिंदम मजूमदार
मुंबई/नई दिल्ली, 20 जनवरी

हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री दुकानों से शराब खरीदने की सीमा को दो बोतल से घटाकर एक करने के वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव से हवाई अड्डों के राजस्व पर असर पड़ेगा और हवाई यात्रा का खर्च बढ़ जाएगा। सरकारी कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा निजी हवाई अड्डे के संचालक सरकार से संबंधित अनुरोध करेंगे और बताएंगे कि शराब बिक्री के राजस्व में कमी आने से इस क्षतिपूर्ति के लिए लैंडिंग तथा पार्किंग शुल्क को बढ़ाना पड़ेगा जिसका अंतिम प्रभाव यात्रियों पर पड़ेगा।

हवाई अड्डे के शुल्क की गणना विमान उतरने तथा पार्किंग जैसी हवाई गतिविधियों तथा ड्यूटी फ्री सामान बिक्री, रेस्त्रां जैसी गैर-हवाई गतिविधियों के कुल योग से की जाती है। गैर-हवाई गतिविधियों से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होने पर विमानन कंपनियों के शुल्क में कमी कर दी जाती है जिसका अंतिम प्रभाव यात्रियों के किराए में कमी के तौर पर देखा जा सकता है।

निजी हवाई अड्डों के एक समूह एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स (एपीएओ) के महासचिव सत्यन नायर कहते हैं, 'विमानन कंपनियों के लिए लैंडिंग तथा पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी से विमान के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है और इससे हवाई यात्राएं और महंगी हो जाएंगी।'

देशभर में हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री बिक्री का आंकड़ा 50 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। दिल्ली तथा हैदराबाद हवाई अड्डे पर गैर-हवाई गतिविधियों से होने वाले राजस्व में खुदरा बिक्री की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तथा शुल्क मुक्त सामान की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है।

सरकार को भेजे गए बजट प्रस्ताव में एपीएओ ने सुझाव दिया है कि भारतीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री सामान के तहत शराब खरीदने की सीमा दो बोतल से बढ़ाकर चार बोतल कर दी जाए जिससे एएआई के राजस्व हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों द्वारा वहन की जाने वाली लागत में कमी आएगी।

वाणिज्य मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री समान की दुकानों से कर मुक्त शराब खरीदने की सीमा घटाकर एक बोतल करने की सिफारिश की है जिससे गैर-जरूरी सामान के आयात को कम किया जा सके।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा, 'यह कम या ज्यादा मात्रा का सवाल नहीं है। एक देश के रूप में हम शराब के आयात को बढ़ावा नहीं दे सकते।'

कारोबारी का पक्ष जाने बगैर नहीं होगा कर का फैसला

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जनवरी

दिल्ली व्यापार एवं कर विभाग ने कारोबारियों को चुनाव के दौरान कर निर्धारण प्रक्रिया में राहत दी है। विभाग ने कर निर्धारण अधिकारियों को चुनाव के दौरान एक पक्षीय निर्धारण नहीं करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान संबंधित कारोबारी का पक्ष जाने बिना कोई भी फैसला नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर दस्तावेज/पत्र/डाक वार्ड या शाखा द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते हैं, तो इन्हें केंद्रीय रीसीट यूनिट में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

कारोबारियों का कहना है कि इस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आचार संहिता लागू होने के कारण अधिकारी भी चुनाव में व्यस्त हैं। दिल्ली व्यापार व कर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों को कारोबारियों को उचित सुनवाई का मौका देना चाहिए। इसलिए चुनाव में ड्यूटी वाले कर निर्धारण प्राधिकारियों को चुनाव के दौरान एकपक्षीय फैसला नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं।

बीएस सूडोकू 3644

		2		4	9		3	
			1	3				7
						5	9	2
				9	3		8	
3								9
	8		7	1				
7	9	5						
6				8	5			
	1		4	7		9		

परिणाम संख्या 3643

9	1	4	6	3	8	5	2	7
3	2	8	1	5	7	6	9	4
7	6	5	4	2	9	8	1	3
5	3	1	2	9	4	7	8	6
8	4	2	3	7	6	1	5	9
6	9	7	5	8	1	3	4	2
4	5	3	8	6	2	9	7	1
1	8	9	7	4	3	2	6	5
2	7	6	9	1	5	4	3	8

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

दिल्ली

सराफा : दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना चार रुपये की मामूली बढ़त के साथ 40,748 रुपये प्रति दस ग्राम पर बोला गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 40,744 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। नीरस कारोबार के बीच चांदी भी सात रुपये की साधारण तेजी के साथ 47,863 रुपये प्रति किलो हो गई जो इससे पूर्व कारोबारी सत्र में 47,856 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी के भाव लाभ के साथ क्रमशः 1,560 डॉलर प्रति औंस और 18.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए।

कानपुर

गेहूं लूज 2090/2100, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4400/4450, तिल सफेद 9000/9200, सोया (टीन) 1550/1600, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1475/1575, सरसों खल 2150/2200, पामोलिन 1600/1625, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1600/1675, अलसी 6500/6600,

लखनऊ

गेहूं दड़ा 2075/2080, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3350, चावल (सोना) 2900/3000

चंदौसी

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1428, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1505, फ्लैक 1450, डीएमओ 1040, टरपीन लैस बोल्ड 1518

मुजफ्फरनगर

गुड़ (40 किलो): लड्डू 1250/1300, खुरपा 1100/1120,चाकू 1050/1150, रसकट 940/950, शक्कर 1280/1300, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3360, सिहोरा 3300, बुंदकी 3280, बुढ़ाना 3345, शामली ×, चीनी हाजिर 3550/3600

हापुड़

गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1100/1125, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4300, खल: सरसों 2250/2300, बिनौला 2450/2550, चना छिलका 2190/2200, चोकर मोटा (34 किलो) 750/760

श्रीगंगानगर

गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3750/3800, जौ 2130/2140, सरसों लूज 4000/4050

जोधपुर

गेहूं 2150/2200, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7300/7375, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1900/1925, चना 4200/4300, काबली चना 5000/6000, मूंग 6900/7000, मोठ 5800/5900, रायडा 3700/3800, मूंगफली 4500/4600, सींगदाना 6000/6500, जीरा 15500/17000, मगज तरबूज 12800/13000, तरबूज बीज ×

जयपुर

अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2100/2110, मक्की 2200/2275, बाजरा 1920/1925, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 2800/2900, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4500/4525, सरसों एक्सपेलर निवाई 9200, कोल्हू कच्ची घानी टोंक 9300, राइसब्रान डिऑयल्ड कंटीन्यूअस 1400, डीओसी (टन): सरसों जयपुर 16500, कोटा 16500,अलवर 16000, निवाई 16200

खन्ना

जीएसटीजीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)126, राइसब्रान (अखाद्य) 123, खल सरसों 1960, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1280, सरसों (टन) 17000, सूरजमुखी (टन) ×, अनाज: गेहूं 2240/2245, आटा (50 किलो)1210, मैदा 1310, चोकर (49 किग्रा) 1060, चोकर (30 किग्रा) 660, मक्की बिहार 2100/2110

बठिंडा

रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4150/4180, हरियाणा 4100/4120, राजस्थान 4060/4120, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2500/2600, सरसों खल 2125/2130, गेहूं चोकर (28 किलो) 595

फाजिल्का

गेहूं 2230/2240, सरसों 4375/4400 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4150/4180, कपास देशी 5150/5225, कपास नरमा (क्विं.) 5300/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2500/2600, जे-34 (चिलकी) 3500/3550

भाषा/एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 288

स्वामीयुक्त नीति

चालू वित्त वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य में भारी कमी की आशंका के चलते सरकार वैकल्पिक रास्ते देख रही है। खबरों के मुताबिक अब वह सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व वाली संपत्ति बेचकर मार्च के अंत तक एक लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। जिन परिसंपत्तियों पर बिक्री के लिए विचार किया जा रहा है उनमें भूमि और पाइपलाइन, सड़क, मोबाइल टावर, बिजली, सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व वाली पारेषण लाइन आदि शामिल हैं। परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का विचार जहां आगे बढ़ाने योग्य है, वहीं सशस्त्र बलों और रेलवे आदि सरकार की विभिन्न शाखाओं के पास शहरी इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी जमीन है जिनके लिए डेवलपर बहुत बड़ी राशि चुकाने को तैयार होंगे। परंतु दी गई अवधि में यह बिक्री करना लगभग असंभव है। इसके अलावा इसके लिए जिस तरह प्रयास किए जा रहे हैं वह बुनियादी रूप से गलत है। पहली बात तो यह लक्षित परिसंपत्तियां मोटे तौर पर सरकारी उपक्रमों की हैं। इन्हें मजबूरी में बेचकर हासिल होने वाली राशि सरकार को लाभांश के रूप में देनी होगी। यह सरकारी उपक्रमों की काम करने की स्वायत्तता के खिलाफ है। दूसरी बात, परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार करने के लिए वित्त वर्ष के लगभग अंत का समय चुना गया है। जाहिर है ऐसा केवल बजट लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया गया है। इसका असर मूल्यांकन और हासिल होने वाली राशि पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं इससे वैधानिक जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं। स्पष्ट है कि सरकार यह विकल्प इसलिए चुनना चाहती है क्योंकि चालू वर्ष में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिखती। इसके लिए भी खराब योजना ही जिम्मेदार है।

चूंकि राजस्व संग्रह में अहम कमी आने वाली है तो ऐसे में विनिवेश के मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन राजकोषीय प्रबंधन को और जटिल बना देगा। चालू वर्ष में सरकार अब तक 18,095 करोड़ रुपये ही जुटा सकी है जो विनिवेश लक्ष्य का 17 फीसदी है। सरकार विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में इसलिए भी संघर्ष करती है क्योंकि वह इस विषय पर व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करती। उदाहरण के लिए यदि सरकार व्यापक रणनीतिक विनिवेश करना चाहती है तो उसे वित्त वर्ष के आरंभ में ही नामों का चयन कर लेना चाहिए। इसे अमल में लाने में समय लगता है क्योंकि संभावित खरीदार उचित जांच-परख करना चाहते हैं। सरकारी उपक्रमों की परिसंपत्ति बेचने का विचार नीति निर्माण में खामी का एक और उदाहरण है।

ऐसे में सही यही होगा कि सरकार ऐसे सरकारी उपक्रमों की सूची तैयार रखे जिनमें वह मध्यम अवधि में विनिवेश करना चाहती है। यह विनिवेश अंशकालिक भी हो सकता है और सामरिक भी। इस प्रक्रिया को अन्य परिसंपत्तियों मसलन भूमि आदि में भी अपनाना चाहिए। इससे न केवल सरकार को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि इससे बाजार भागीदारों को तैयारी और बोली लगाने के लिए उचित समय भी मिलेगा। ऐसी प्रक्रिया अपनाने से बोली लगाने वालों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मूल्यांकन सुधरेगा। इससे सरकार को भी इस बात का बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि मध्यम अवधि में पैसा कैसे जुटाया जा सकता है। आदर्श स्थिति में परिसंपत्ति बिक्री को पूरी तरह घाटे में पूर्ति करने के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया से हासिल राजस्व का इस्तेमाल नई परिसंपत्तियां तैयार करने में किया जाना चाहिए। इससे मध्यम से दीर्घ अवधि में संभावित वृद्धि को तेज करने में मदद मिलेगी।

बिनय सिन्हा

थोड़ी स्थिरता हासिल मगर जोखिम बाकी

धीरे-धीरे वृद्धि में स्थिरता आ रही है लेकिन अभी भी कई चक्रीय कारक मौजूद हैं जिनका जोखिम बरकरार है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

मांग में कमी से उत्पन्न आर्थिक मंदी की इकलौती अच्छी बात यह है कि माल कम करने से वह समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कटौती अनंतकाल तक जारी नहीं रखी जा सकती है। बीती छह तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जो गिरावट आई है उसकी एक अहम बात है इन्वेंटरी में गिरावट। जीडीपी में जब गतिविधियों का आकलन किया जाता है तो इन्वेंटरी का आकार वृद्धि में जोड़ा जाता है। कम इन्वेंटरी का असर उलटा होता है। बीती छह तिमाहियों में सेवा और उद्योग जगत में वृद्धि के अंतर तथा जीएसटी संग्रह में कमी में इसे महसूस किया जा सकता है। तिमाही सेवा वृद्धि के आकलन में दिक्कत हो सकती है लेकिन इसमें उद्योग की तरह गिरावट नहीं आई है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेवा क्षेत्र में ज्यादा इन्वेंटरी नहीं हो सकती।

इससे पहले ऐसा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत के पहले वाली तिमाही में देखने को मिला था। उस वक्त उद्योग और सेवा की वृद्धि में समान भिन्नता नजर आई थी। वस्तु आपूर्ति श्रृंखला ने इन्वेंटरी कम करके जीएसटी के साथ नई शुरुआत करने की सोची। बीती पांच तिमाहियों में ऐसा वित्तीय हालात तंग होने से हुआ। क्योंकि इसका असर वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा कारोबारियों को ऋण की उपलब्धता पर पड़ा।

ऐसे प्रमाण हैं कि माल में कमी का दौर अब समाप्त हो चुका है। बिजली की मांग वृद्धि जो अक्टूबर और नवंबर में दो अंक में थी वह दिसंबर में केवल 2 फीसदी कम रही। जनवरी के पहले सप्ताह में इसमें मामूली इजाफा हुआ। जीएसटी संग्रह और रेल मालवहन भी सकारात्मक वृद्धि दर्शा रहे हैं। ये आंकड़े अभी भी कमजोर हैं लेकिन पहले आई तीव्र कमी से तो बेहतर ही हैं। यदि बाकी सब सामान्य रहा तो एक बार फिर इन्वेंटरी भरनी शुरू हो जाएगी और इसका लाभ वृद्धि को मिलेगा।

परंतु वित्तीय स्थिति तंग बनी हुई है। जिन वित्तीय कंपनियों के पास पूंजी, उत्पाद और पूंजी तक पहुंच है वे भी वृद्धि में धीमेपन के चलते ऋण देना कम कर रही हैं। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर आधी हो जाने के बाद यदि मौजूदा कर्जदारों के लिए ऋण की गुणवत्ता का नए सिरे से आकलन किया जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा व्यय में कटौती वृद्धि की राह में एक और बाधा होगी क्योंकि वे ऐसे वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे जहां कर प्राप्ति तय लक्ष्य से कम रही हो। पहले आठ महीनों के दौरान केंद्र सरकार का व्यय 13 फीसदी बढ़ा। लेकिन प्राप्तियों में कमी को देखते हुए यदि यह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहा तो अंतिम चार महीनों में व्यय पिछले साल से एक फीसदी कम होगा। यदि विनिवेश प्रक्रिया बजट से कमजोर रही तो कहीं अधिक बड़ी कमी उत्पन्न हो जाएगी। राज्य सरकारों के लिए वित्त वर्ष के मध्य तक ऋण के लक्ष्य स्थिर हो जाते हैं और वे अपने घाटे में और इजाफा नहीं कर सकतीं। उनके लिए व्यय में कटौती करना आवश्यक है। वे पहले ही भुगतान करने में देरी कर रही हैं। उदाहरण के लिए फसल बीमा का नुकसान। बल्कि वित्त वर्ष के अंत तक राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी देरी हो सकती है। ऐसे कदमों से कमजोर उपभोक्ता रुझान और कमजोर हो सकते हैं और कंपनियों की निवेश योजनाएं और कमजोर हो सकती हैं।

कई नैसर्गिक स्थिरता प्रदान करने वाले कारक अब काम नहीं कर रहे हैं। कमजोर आर्थिक वृद्धि प्राय: ब्याज दरों को प्रभावित करती है लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते आए हैं कमजोर वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के बावजूद कर्जदारों के लिए ब्याज दर अपरिवर्तित रही है।

गत वर्ष देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी जीडीपी के दो फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूंजीगत आवक और निर्यात तब भी बढ़े जब कमजोर घरेलू मांग से आयात कम हुआ। यदि विदेशी बचतकर्ता देश की जरूरत से अधिक धन देना चाहते हैं तो या तो मुद्रा का अधिमूल्यन होगा या फंड की लागत घटेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड खरीदने का एक जोखिम यह है कि मुद्रा कमजोर होगी लेकिन भुगतान संतुलन का ऐसा अधिशेष दिखाता है कि फिलहाल ऐसा कोई जोखिम नहीं है।

आम चर्चा की बात करें तो बीते कुछ महीनों में बैलेंस शीट की समस्याओं की तादाद बढ़ी है। वह सही हो सकती है और हमें यह याद रखना चाहिए कि बैलेंस शीट पर दबाव कमजोर वृद्धि के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा चोरी या भ्रष्टाचार के कारण हो। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार का 45 प्रतिशत का ऋण-जीडीपी अनुपात स्थायी नजर आया और उसमें निरंतर गिरावट आ रही है क्योंकि नॉमिनल वृद्धि दर ऊंची रही लेकिन वृद्धि में धीमापन आने और ऋण की लागत के करीब 7 फीसदी तथा ब्याज दर के जीडीपी के 3 फीसदी रहने के कारण जीडीपी अचानक खस्ता नजर आने लगी। गत वर्ष ये वृद्धिकारी व्यय का तिहाई था। यदि कर 8 फीसदी की दर से बढ़ते हैं और नॉमिनल जीडीपी के अनुरूप गैर विवेकाधीन व्यय मसलन ब्याज और वेतन आदि उसी गति से बढ़ते हैं तो राजकोषीय समावेशन कैसे होगा? अतिरिक्त व्यय की तो बात ही छोड़ दी जाए। यदि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि में आया धीमापन तनावग्रस्त ऋण को बढ़ावा देता है तो सही उपाय यही होगा कि वृद्धि को गति प्रदान की जाए, न कि बैलेंस शीट सुधारने की कवायद की जाए।

आर्थिक कारक समय-समय पर अपनी भूमिका निभाते हैं भले ही यह वांछित से धीमी गति से हो।

कम ब्याज दर पर बात करें तो वृद्धि में सुधार के लिए वह आवश्यक है। बैंक जमा दर में गिरावट आने लगी है और समय बीतने के साथ इसका असर ऋण दर पर भी पड़ेगा। मोर्गेज दर बीते पांच महीने में करीब 50 आधार अंक कम हुई है। बजट प्रस्तुत होने के बाद राजकोषीय घाटे और व्यय को लेकर अनिश्चितता कुछ हद तक कम होगी। अप्रैल के बाद केंद्र और राज्य सरकारें व्यय सुधारने में कामयाब हो सकती हैं। तब तक संभवत: शीर्ष मुद्रास्फीति भी सार्थक सुधार के साथ नजर आए। यदि वित्तीय तंत्र में कोई और गड़बड़ी नहीं होती है तो ऋण विस्तार में भी गिरावट आएगी, भले ही यह धीमी गति से हो। अर्थव्यवस्था शायद धीमी गति से स्थिरता हासिल करे, वृद्धि मौजूदा स्तर से थोड़ी सुधर सकती है, हालांकि वह वांछित लक्ष्य से फिर भी कोसों दूर रहेगी।

(लेखक क्रेडिट स्विस में इंडिया स्ट्रैटिजिस्ट और एशिया पैसिफिक स्ट्रैटिजी के को-हेड हैं)

सेना के तीनों अंगों की एकीकृत थिएटर कमान पर विचार जरूरी

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

सेना के उच्च प्रबंधन को मजबूत करने की चर्चाओं में आम तौर पर दो सुधारों की जरूरत पर सहमति होती है। पहली जरूरत सेना के तीनों अंगों- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बिठाने के लिए एकीकृत प्रमुख की नियुक्ति है। भारत के पहले सैन्य बल प्रमुख (सीडीएस) की नियुक्ति के साथ आंशिक तौर पर इसे पूरा किया जा चुका है। सीडीएस को तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने का जिम्मा दिया गया है लेकिन वह ट्राई-सर्विस मसले पर ही सरकार को परामर्श देगा और तीनों सेनाओं के प्रमुख अपने बल के बारे में पहले की तरह सलाह देते रहेंगे।

अधिकतर विशेषज्ञ इस जरूरत पर सहमत हैं कि तीनों सेनाओं को साथ आकर ट्राई-सर्विस लड़ाकू कमान बनानी चाहिए। एक भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं की कमान अलग होती है, मसलन सेना की उत्तरी कमान, वायुसेना की पश्चिमी कमान और नौसेना की दक्षिणी कमान। तर्क यह रहा है कि तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान बनाकर यह अलगाव खत्म किया जाए। इस कमान को जंग की स्थिति में लड़ाकू अभियान चलाने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जरूरी सभी अधिकार होंगे। अंडमान एवं निकोबार कमान में ऐसी एकीकृत कमान पहले से मौजूद है लेकिन उस प्रायोगिक अनुभव को आगे नहीं बढ़ाया गया। एकीकृत कमान की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका ने लागू की थी। उसने 1947 में पांच क्षेत्रों के लिए पांच युद्धक कमान गठित की थी। मध्य कमान, अफ्रीका कमान और हिंद-प्रशांत कमान जैसे नाम पूरी दुनिया को ही कवर करते थे। चीन की सेना ने भी 2016 में यह मॉडल अपनाते हुए पांच संयुक्त थिएटर कमान में पुनर्गठन किया।

साझा नेतृत्व जहां सैन्यबलों के पुनर्गठन और उपकरणों की खरीद में किफायत बरतने में मदद करता है, वहीं साझा थिएटर कमान ढांचा लागू करने के पहले काफी सोच-विचार करना होगा। भारतीय वायुसेना ने थिएटर कमान व्यवस्था का लगातार विरोध किया है। हमें उसकी दलीलों पर ध्यान देना चाहिए।

पहली, लड़ाकू विमानों के तीव्र रफ्तार से उड़ान भरने और तेजी से भौगोलिक दायरा बदलने को आधार बनाते हुए वायुसेना कहती है कि पूरा भारत एक ही भौगोलिक थिएटर है। वहीं अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार वाली थलसेना और नौसैनिक पोतों को भौगोलिक आधार पर एक समूह में रखना तर्कसंगत लगता है। लेकिन यह भी सही है कि लड़ाकू विमान जिस तरह मिनटों में ही दूसरी जगह जा सकते हैं, उसी तरह वे एक से दूसरी लड़ाकू भूमिका भी अपना सकते हैं। पाकिस्तान में बालाकोट के आतंकी शिविर पर गत फरवरी में हुए हमले के दौरान मिराज-2000 विमानों ने मध्य कमान में स्थित ग्वालियर से उड़ान भरी थी और पश्चिमी थिएटर से भी दूर के निशाने पर धावा बोला था। उस अंतर-थिएटर अभियान में मिराज विमानों ने 1,500 किलोमीटर से अधिक उड़ान भरी और हवा में ही ईंधन भरा गया।

ऐसे ही किसी अभियान में लड़ाकू विमान ग्वालियर से उड़ते हुए पूर्वी थिएटर में जाकर मैकमोहन रेखा के पार भी हमला कर सकते हैं। इसमें उड़ान भरने से लेकर निशाना लगाने तक केवल एक घंटे का वक्त लगेगा और हवा में ईंधन भरने की भी सीमित जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि मिराज-2000 विमान वापस लौटते समय आसानी से तेजपुर या चाबुआ के एयरफोर्स स्टेशन पर उतरकर ईंधन भर सकते हैं। एक लड़ाकू विमान के लिए दूसरे कमान क्षेत्र में जाकर कार्रवाई करना बेहद आसान है।

दूसरी, ऐसे अभियानों में अलग-अलग थिएटरों के बीच समन्वय बनाना कठिन है। पाकिस्तान और चीन के हवाई क्षेत्र में जाकर हमला करने के लिए आज एक पूरा पैकेज चाहिए। हमलावर विमान को वायु प्रतिरक्षा एस्कार्ट, इलेक्ट्रॉनिक जंगी विमान, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली की भी जरूरत होगी। यह पैकेज कई एयरबेस से जुटाए विमानों से ही तैयार होगा क्योंकि एक बेस में सभी मौजूद नहीं होती हैं। ऐसे में सभी तरह के विमानों के उड़ाने भरने में बेहद सटीक समन्वय जरूरी होगा ताकि तय समय पर वे उपलब्ध रहें। लेकिन अलग-अलग थिएटर कमान में बांटे जाने पर ऐसा होना मुश्किल होगा। हरेक थिएटर कमांडर अपने काम को सबसे आगे रखेगा और दूसरे थिएटरों में हमले के लिए संसाधन देने में हिचकेगा।

तीसरी, वायुसेना की युद्धक क्षमता महज 28 स्क्वाड्रन है। इन्हें अगर तीन या चार थिएटरों में बांट दिया जाए तो स्थिति कमजोर हो जाएगी। विशाल वायुसेनाएं ही अपने विमान अलग थिएटर कमान में देने का जोखिम उठा सकती हैं। भारत का हवाई क्षेत्र चीन के पश्चिमी थिएटर कमान से भी छोटा है, लिहाजा भारतीय वायुसेना एक थिएटर का ही हिस्सा रह सकती है।

चौथी, एकल थिएटर आधार पर परिचालन के लिए वायुसेना को नियंत्रण एवं नियोजन केंद्रीकृत करना होगा जबकि क्रियान्वयन को विकेंद्रित रखना होगा। जंगी स्क्वाड्रनों के अपने स्थायी ठिकाने हैं लेकिन किसी भी थिएटर में अभियान अंजाम देने के लिए एक पायलट को दूसरी जगहों पर भेजकर अनुभव दिलाना होगा। इस तरह का लचीलापन लाना मुश्किल होगा।

पांचवीं, भारत के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वायुसेना को केंद्रीकृत नियंत्रण की जरूरत है। वायु सुरक्षा निगरानी को स्वचालित नेटवर्क आईएसीसीएस से अंजाम दिया जाता है। एस-400 और एमआर-सैम प्रणालियों के इस साल लागू हो जाने पर स्थिति साफ हो जाएगी। अंतरिक्ष की निगरानी के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण चाहिए।

वैसे सीडीएस ने कहा है कि भारत एकीकृत थिएटर कमान में दूसरे देशों की आंख मूंदकर नकल नहीं करेगा और फैसला पूरी तरह देश की जरूरतों पर आधारित होगा। यह भी सच है कि सेना की अधिकांश कमान में नौसेना की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में हमें एकीकृत ट्राई-सर्विस ढांचा बनाने के बजाय इस बारे में सोचना चाहिए कि युद्ध शुरू होने पर तीनों सेनाओं की समन्वित मारक क्षमता किस तरह बढ़ाई जा सके।

कानाफूसी

सीएए का समर्थन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के भारी विरोध को देखते हुए देशव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि की उपस्थिति में होगा। ये नेता सीएए के समर्थन में आयोजित रैलियों को संबोधित करेंगे। 21 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। यह सभा उत्तर प्रदेश में इस चरण में बनी छह जन सभाओं में से पहली होगी। इस रैली में मध्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। राज्य पार्टी संगठन ने यह दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है कि ज्यादातर लोग इस नए कानून के समर्थन में हैं। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का कई राज्यों के लोग पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं।

आमने-सामने

पत्रकारों के प्रतिनिधि संगठन वित्त मंत्रालय की रिपोर्टिंग करने वाले अधिमान्य संवाददाताओं के नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश पर लगी रोक हटवाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने जा रहे हैं। भारतीय प्रेस परिषद ने इस संबंध में भारतीय प्रेस क्लब और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब समेत विभिन्न पत्रकार संगठनों की शिकायत सुनने का निर्णय किया है। वित्त मंत्रालय ने रोक गत वर्ष जुलाई में लगाई थी। संवाददाताओं का कहना है कि इस आदेश के बाद अफसरशाह आधिकारिक रूप से उनसे मिलने में भी घबराने लगे हैं। उनका यह भी कहना है कि अन्य मंत्रालयों में अधिमान्य संवाददाताओं के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है।

आपका पक्ष

अर्थव्यवस्था की स्थिति और बजट

भारत की जीडीपी दर पांच साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की जीडीपी दर के पूर्वानुमान में कमी कर रही हैं। विशेषज्ञ मौजूदा स्थिति के लिए निवेश में कमी को कारण मान रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी निवेश की कमी से जूझ रही है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई प्रयास किए हैं जैसे निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कॉरपोरेट कर में कटौती, बैंकों का विलय, बैंकों को नई पूंजी देने, जीएसटी दर में कटौती और रीपो दर में कटौती का अभी तक कुछ खास असर नहीं दिखा है। प्रयासों की श्रृंखला में आगामी बजट में वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निजी निवेश पर निर्भर रहने की अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर चुनौती है तो इसके लिए समाधान भी हैं। इसमें प्रमुख उपायों के रूप में कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा की जा सकती है। आर्थिक सुस्ती के परिणामस्वरूप रोजगार की स्थिति और बिगड़ गई है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया आदि ने कुछ हद तक रोजगार सृजन का काम किया है। लेकिन आर्थिक सुस्ती ने इन योजनाओं के प्रभाव को सीमित कर दिया है, जबकि स्वरूप में बदलाव से मनरेगा जैसी रोजगारमूलक योजना को संपत्ति सर्जक योजना बना दिया है। इसमें सुधार के लिए बजट में मनरेगा को लेकर कुछ घोषणा संभव है। इसके अलावा कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा भी की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र को वित्तपोषण को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार आदि में निवेश करने से इस क्षेत्र को मंदी के प्रभाव से उभरने में काफी मदद मिलेगी। आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मांग, खपत और निवेश को बढ़ाया जाए। अन्य उपायों में बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ाना, आयकर की दरों में कटौती, वित्तीय क्षेत्र मुख्यत: एनबीएफसी में सुधार किया जाना आवश्यक है तभी अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों से निपटते हुए 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपेक्षित विकास दर को बनाए रखा जा सकता है।

सुजीत कुमार, बिलासपुर

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में अलग प्रावधान करने चाहिए

राजनीतिक तौर पर जागरूकता जरूरी

देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। इसकी तैयारी राजनीतिक पार्टियों ने कर दी है। मुख्यतौर पर आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और भारतीय जनती पार्टी (भाजपा) मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई वादे कर रही हैं। इसके लिए कुछ राजनीतिक दल बड़ी-बड़ी रैलियां करेंगें तो कुछ जनसभाएं करेंगे, कुछ घर-घर जाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगें। मतदाताओं को जागरूक होकर मतदान करना चाहिए। किसी भी लालच में आकर मतदान नहीं करना चाहिए। मतदाताओं को यह सोच एवं परख लेना चाहिए कि जिसे वह अपना मत देने जा रहे हैं उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है या वह दागी नेता तो नहीं है। एक गलत वोट का प्रयोग पांच साल तक पछतावा ही देता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

एथनॉल के लिए दूसरी निविदा जारी

तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल में मिलाने के लिए चीनी मिलों से मांगा 2.53 अरब लीटर एथनॉल

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 20 जनवरी

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की अगुआई में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने पेट्रोल में मिलाने के लिए 2.53 अरब लीटर घरेलू एथनॉल आपूर्ति के लिए दूसरी निविदा जारी की है। पहली निविदा में चीनी मिलों द्वारा अपेक्षित एथनॉल की एक-तिहाई से भी कम मात्रा का आश्वासन दिए जाने के बाद यह दूसरी निविदा जारी की गई है।

इस निविदा में 1 फरवरी से 30 नवंबर, 2020 के बीच एथनॉल की आपूर्ति की जानी है। इस निविदा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) की 1.07 अरब लीटर की मांग भी शामिल है। बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) ने घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से गन्ने के रस, चीनी या चाशनी, बी-भारी या सी-भारी शीरे अथवा क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से निर्मित क्रमश: 67.2 करोड़ लीटर और 78.7 करोड़ लीटर एथनॉल की मांग की है।

हालांकि विशेषज्ञों को इस सत्र की पहली एथनॉल निविदा के लिए मिली बेहद खराब प्रतिक्रिया के बाद दूसरी निविदा की सफलता पर संदेह है। तेल विपणन कंपनियों ने अपनी पहली निविदा में 5.11 अरब लीटर एथनॉल की मांग की थी जिसमें से चीनी मिलों ने गन्ने की कम आपूर्ति के बाद इस साल अपने उत्पादन में गिरावट के अनुमान की वजह से केवल 1.56 अरब लीटर के लिए ही अनुबंध किए थे। चीनी मिलों से कम आपूर्ति के कारण एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम प्रभावित हुआ था।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि अगर चीनी मिलें पिछले साल तेल विपणन कंपनियों को की गई एथनॉल आपूर्ति की मात्रा के स्तर तक पहुंच पाती हैं, तो हमें खुशी होगी।

तेल विपणन कंपनियों ने सितंबर 2019 में चीनी मिलों से एथनॉल के लिए अपनी पहली निविदा जारी की थी। चीनी मिलों द्वारा कम मात्रा की पेशकश किए जाने के कारण तेल विपणन कंपनियों ने 1.56 अरब लीटर एथनॉल को अंतिम रूप दिया था। इसमें बी-भारी शीरे से 61.63 करोड़ लीटर और गन्ने के रस से 10.6 करोड़ लीटर एथनॉल शामिल था।

तेल विपणन कंपनियां पर्यावरण अनुकल ईंधन के रूप में सीधे पेट्रोल में मिलाने के लिए एथनॉल की खरीद करती हैं। इससे कच्चे तेल के आयात में इसी अनुपात में कमी आती है और चीनी मिलों को इस उप-उत्पाद से ज्यादा कमाई करने का प्रोत्साहन भी मिलता है। इस साल मॉनसून की बाढ़ में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा था जिससे गन्ने की उपलब्धता कम हो गई।

इस्मा द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े बताते हैं कि तेल विपणन कंपनियों ने पिछले पेराई सत्र (अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019) में 3.32 अरब लीटर एथनॉल के लिए निविदा जारी की थी। इसमें से तेल विपणन कंपनियों ने 2.39 अरब लीटर एथनॉल आपूर्ति को अंतिम रूप दिया था और उन्होंने 2.45 अरब लीटर के लिए अनुबंध किया था। तेल विपणन कंपनियों ने पिछले पेराई सत्र के दौरान केवल 1.87 अरब लीटर एथनॉल ही उठाया था। हालांकि मौजूदा सत्र के लिए एथनॉल की जरूरी मात्रा बढ़ गई है क्योंकि तेल विपणन कंपनियां पांच प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद कर रही हैं।

वर्मा ने कहा कि कई चीनी मिलों ने अपनी स्वतंत्र डिस्टिलरी स्थापित कर ली हैं और भविष्य में आपूर्ति में इजाफा करने के लिए मौजूदा डिस्टिलरी की क्षमता में विस्तार कर दिया है। द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक विजय बांका ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 100 केएलपीडी (हजार लीटर प्रति दिन) वाले नए डिस्टिलरी संयंत्र की शुरुआत की है।

गन्ने की कम उपलब्धता से भी चीनी उत्पादन पर असर पड़ रहा है। इस्मा ने 1 अक्टूबर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 की अवधि के दौरान देश का चीनी उत्पादन 26 प्रतिशत गिरकर 1.086 करोड़ टन रहने की सूचना दी है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में उत्पादन 1.474 करोड़ टन था।

एथनॉल मिश्रण

- इस निविदा के तहत 1 फरवरी से 30 नवंबर, 2020 के बीच की जानी है एथनॉल की आपूर्ति
- इस सत्र की पहली एथनॉल निविदा में मिली थी बेहद खराब प्रतिक्रिया
- गन्ने की कम उपलब्धता के कारण एथनॉल की आपूर्ति पर पड़ रहा असर
- तेल विपणन कंपनियों ने पहली निविदा में की थी 5.11 अरब लीटर मांग, चीनी मिलों ने किए थे केवल 1.56 अरब लीटर के लिए ही अनुबंध

बंदरगाहों पर फंसा पाम तेल

रॉयटर्स
कुआलालम्पुर/मुंबई, 20 जनवरी

खाद्य तेल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार भारत द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हजारों टन रिफाइंड पाम तेल देश के अलग-अलग बंदरगाहों पर अटका हुआ है या उसकी ढुलाई में देरी हो रही है। प्रमुख आपूर्तिकर्ता मलेशिया के साथ कूटनीतिक विवाद के बीच यह प्रतिबंध लगाया गया था। विभिन्न सूत्रों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले उद्योग के एक अधिकारी के अनुसार घरेलू रिफाइनरों की मदद के लिए उनके संयंत्रों की क्षमता दर बढ़ाने की खातिर भारत ने 8 जनवरी को रिफाइंड पाम तेल आयात पर रोक लगाने की घोषणा की थी। सामान्य तौर पर भारत साबुन से लेकर बिस्किट तक हर चीज में इस्तेमाल किए जाने वाले वनस्पति तेल की अपनी लगभग पूरी आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहता है।

रिफाइनिटिव के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक और निर्यातक देश मलेशिया ने सार्वजनिक तौर पर भारत के कदम का विरोध किया था। दूसरी ओर भारत ने इंडोनेशिया से आयात के लिए ऑर्डर बढ़ा दिए है। पिछले पांच सालों से भारत मलेशिया का सबसे बड़ा बाजार रहा है और इस विवाद से मलेशिया के बेंचमार्क पाम के वायदा भाव में शुक्रवार को सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आई और यह पिछले 11 साल से भी ज्यादा अवधि के दौरान सबसे खराब सप्ताह रहा।

मुंबई के वनस्पति तेल एक कारोबारी ने कंपनी की नीतियों का हवाला देते हुए नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि 30,000 टन से ज्यादा रिफाइंड तेल (देश के) विभिन्न बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। इन सब जहाजों पर लदाई सरकार द्वारा रिफाइंड पाम तेल आयात पर पाबंदी लगाए जाने से पहले की गई थी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सीमा शुल्क अधिकारी उन जिंसों को उतारने की अनुमति दे देते हैं जो नियमों में किसी भी बदलाव से पहले रास्ते में होती हैं। लेकिन रिफाइंड पाम तेल के मामले में कुछ दुविधा है और इसी से देरी हो रही है। इस मामले की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी रखने वाले नई दिल्ली के एक सूत्र ने कहा कि इस प्रतिबंध का मतलब यह है आयातकों को खरीद के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। यह वह उपाय है जिसका इस्तेमाल मलेशिया से आने वाली खेपों को नामंजूर करने या उनमें देरी करने के लिए किया जा सकता है। इस व्यक्ति ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए पहचान बताने से मना कर दिया।

एक अन्य वनस्पति तेल आयातक ने कहा कि कुछ जहाज पूर्वी भारत में कोलकाता बंदरगाह पर फंस गए हैं, जबकि कुछ जहाज पश्चिमी तट पर फंसे हुए हैं। आयातक ने कहा कि पश्चिमी तट पर मैंगलोर बंदरगाह पर एक घटना में कच्चे पाम तेल को एक जहाज से उतारा गया है, जबकि रिफाइंड तेल के लिए अनुमति नहीं दी गई है। रॉयटर्स को यह नहीं पता चल पाया कि कोलकाता और मंगलूरू में जिन जहाजों को रोका गया है, वे कौन-से जहाज हैं और खरीदार कौन है। कुआलालम्पुर में एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह रिफाइंड तेल इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही देशों से आया है।

जवाबी कदम नहीं उठाएगा मलेशिया

मलेशिया पाम तेल की खरीद का भारत द्वारा बहिष्कार किए जाने के मामले में उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने सोमवार को कहा कि उनका देश इतना छोटा है कि वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। महातिर ने लैंगकावी में संवाददाताओं से कहा कि इससे निपटने के लिए हमें रास्ते और उपाय तलाशने होंगे। महातिर भारत की घरेलू नीतियों के खिलाफ टिप्पणी करते रहे हैं जिससे खाद्य तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत ने अपने सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता मलेशिया से आयात रोक दिया। *रॉयटर्स*

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 20	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,796.0	3.9	2,067.2	8.1
Copper	6,276.5	9.1	6,581.4	9.4
Nickel	13,840.0	-16.0	14,765.9	-13.9
Lead	1,977.0	-10.6	2,207.8	4.7
Tin	17,775.0	5.3	18,562.8	4.0
Zinc	2,434.0	-2.2	2,657.9	1.1
Gold ($/ounce)	1,559.5*	4.7	1,747.4	4.7
Silver ($/ounce)	18.1*	2.8	20.4	3.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	65.0*	10.2	64.6	7.6
Natural Gas ($/mmBtu)	1.9*	-17.2	1.9	-16.0
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	195.3	10.8	316.3	8.7
Maize	192.6*	4.0	335.3	12.2
Sugar	401.0*	19.4	492.0	0.5
Palm oil	765.0	43.0	1,237.5	43.2
Rubber	1,523.6*	10.9	1,940.7	14.1
Coffee Robusta	1,290.0*	6.1	1,778.9	-6.6
Cotton	1,570.8	9.3	1,631.3	0.8

* As on Jan 20, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.1& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	65.8	32805
Oil and Oilseeds	313.1	85331
Spices	3.2	10
Metal(Jan 17)		
Metal- non ferrous	4988.2	50081
Metal- precious	9505.0	405
Oil and gas(Jan 17)		
Gas	3324.7	69066
Oil	11956.2	1472

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	209.2	123369
Grains	103.9	98080
Oil and Oilseeds	664.0	497430
Others	76.6	66555
Pulses	137.2	28310
Spices	40.9	22839

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Jan 31)	802.1	1.7
Nickel (Jan 31)	1024.0	0.9
Silver (Mar 05)	46756.0	0.7
Silver Mini (Feb 28)	46768.0	0.7
Silver Micro (Feb 28)	46765.0	0.7
Gold (Feb 05)	39946.0	0.7
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	142.8	-6.2
Cardamom (Feb 14)	3951.0	-3.7
Mentha Oil (Jan 31)	1253.6	-0.8
Kapas (Apr 30)	1125.0	-0.7
Cotton (Jan 31)	19720.0	-0.7
Crude Oil (Jan 17)	4159.0	-0.1

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Soyabean Indore (Jan 20)	4236.0	0.8
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	908.2	0.4
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2106.0	0.1
Losers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6246.0	-2.5
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4226.0	-2.4
Chana-Bikaner (Jan 20)	4410.0	-1.3
Moong-Mertacity (Jan 20)	7440.0	-1.3
Wheat-Kota (Jan 20)	2249.0	-0.9
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4106.0	-0.8
Coriander-Kota (Jan 20)	6306.0	-0.8
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1126.0	-0.7
Jeera Unjha (Jan 20)	15825.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3951.0	1.8
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	1.5
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19720.0	1.4
Lead Mum (May 29)	155.6	0.5
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46765.0	0.3
Silver Ahm (Mar 05)	46756.0	0.3
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1253.6	-9.9
Alumini-Mumbai (Jan 31)	140.6	-4.0
Lead Min Mumbai (Jan 31)	151.8	-1.9
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	184.0	-1.8
Copper Mum (Jan 31)	454.6	-1.1
Nickel Mumbai (Jan 31)	1024.0	-1.0

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2020.0	3.2
Bajra-Delhi (Jan 20)	2020.0	2.5
Maize-Sangli (Jan 20)	2021.0	2.4
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6246.0	1.5
Barley Jaipur (Jan 20)	2189.0	0.5
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6306.0	-8.5
Moong-Merta City (Jan 20)	7440.0	-4.2
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3202.0	-3.0
Soy Bean Indore (Jan 20)	4236.0	-2.8
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7200.0	-2.4
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	777.4	-1.0

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals .....Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg 109.....(109)
Aluminium ingots /kg 147.....(147)
Brass sheet cutting /kg 329.....(327)
Brass utensil scraps/kg 313.....(312)
Copper heavy scrap /kg 435.....(435)
Copper utensil scraps/kg 406.....(406)
Copper wire bar /kg 468.....(468)
Lead ingots /kg 157.....(157)
Nickel Cathodes /kg 1050.....(1050)
Tin slabs /kg 1320.....(1315)
Zinc slabs /kg 189.....(187)
Source:Bombay Metal Exchange

Cotton .....Mumbai
Bengal Deshi /Qtl 10292.....(10264)
DCH - 32 /Qtl 11529.....(11501)
Jaydhar /Qtl 9926.....(9983)
Shankar- 6 /Qtl 11304.....(11304)
Source:Cotton Association of India

Oil .....Mumbai
Castor FSG /10kg 883.....(877)
Castor Comm /10kg 873.....(867)
Ricebran oil/10kg 820.....(820)
Groundnut oil /10kg 1140.....(1140)
Linseed oil /10kg 965.....(975)
Karanji /10kg 800.....(800)
Palm oil /10kg 850.....(865)
Sunflower exp ref /10kg 905.....(915)
Sunflower oil exp /10kg 880.....(890)
Soyabean ref / 10kg 895.....(905)
Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar .....Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl 3412-3585 .....(3412-3585)
Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel .....
NYSE Crude 58.71.....(58.54)
Brent Crude (UK) 64.74 .....(65.18)
Brent Crude (WTI) 58.54.....(58.54)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu 1.94 .....(2)
Furnace/ 180 Cst &/bbl 331.91 .....(335.3)
Naptha spot /Rs/MT 45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T. 36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L. 33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold .....Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms 39951.....(39809)
Pure (99.90 Purity) /10 gms 40112.....(39969)
Silver.999/ kg 46640.....(46555)

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19405.25	19473.80
Alumini-Mumbai (M)	1 K	144.90	146.35
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1985.00	1970.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1971.25	1957.50
Barley Jaipur (N)	1 Q	2187.80	2177.75
Cardamom-Vand. (I)	1 K	4050.00	3900.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4197.00	4213.90
Castor Seed-Kadi (N)	X	4175.00	4175.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4377.50	4219.65
Chana Delhi (N)	1 Q	4534.15	4474.05
Chana-Akola (N)	X	4350.00	4200.00
Coriander-Gondal (N)	X	6633.00	6644.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6900.00	6813.75
Coriander-Kota (N)	1 Q	6895.80	6891.65
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2125.00	2125.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2097.60	2098.30
Cotton-Kadi (N)	1 B	19266.05	19472.20
CPO-Kandla (M)	10 K	792.70	807.60
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	773.75	785.45
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	800.00	790.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	904.40	902.15
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1547.35	1544.00
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3443.55	3437.55
Gold Ahm (M)	10 G	39804.00	39947.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31971.00	32086.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3997.00	4010.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7303.60	7377.95
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4010.85	4043.65
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4025.00	4070.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1144.40	1138.85
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	102.65	103.40
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16200.00	16500.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15909.10	15883.35
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	896.90	900.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1053.60	1060.45
Kapas-Rajkot (N)	X	1061.25	1066.25
Lead Mum (M)	1 K	155.50	154.70
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1970.65	1966.65
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2357.50	2313.35
Maize-Erode (N)	X	2045.00	1995.85
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2200.00	2205.00
Maize-Sangli (N)	X	2020.00	1973.10
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4900.00	4937.50
Moong-Merta City (N)	1 Q	7818.75	7770.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4462.75	4488.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	1040.90	1034.80
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3229.00	3229.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3300.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	340.90	341.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34260.00	34284.60
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	885.00	885.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	792.00	779.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1931.95	1900.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5226.75	5195.50
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	877.50	880.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	902.15	908.20
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	906.30	903.70
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	927.50	919.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13800.00	13800.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13767.00	13800.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46527.00	46617.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4335.00	4359.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4279.90	4280.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4393.50	4413.70
Soy Bean-Akola (N)	X	4271.00	4293.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34475.00	34680.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	910.00	911.70
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32200.00	32300.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32100.00	32200.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29440.00	29500.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3287.50	3275.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3401.00	3394.80
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3324.10	3293.15
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3476.20	3485.70
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3340.00	3320.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3175.90	3160.65
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6152.50	6152.50
Wheat Delhi (N)	1 Q	2350.00	2268.90
Wheat Kota (N)	1 Q	2255.00	2181.50
Wheat New Indore (N)	1 Q	2300.00	2250.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2177.50	2105.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2350.00	2250.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5650.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5975.00	5900.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.80	187.25

* as on Jan 17, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (सोमवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19960, 19960, 19690, 19720	3214	502	18061
Feb 28	20180, 20220, 19990, 20000	2190	343	12151
Mar 31	20350, 20350, 20270, 20280	85	12	1747
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2106, 2125, 2083, 2106	830	46	2030
Feb 20	2136, 2136, 2063, 2071	70050	4400	95310
Mar 20	2148, 2154, 2091, 2096	11390	966	15230
Apr 20	2174, 2174, 2118, 2125	1810	168	5900
May 20	2182, 2186, 2157, 2172	180	18	520
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1137, 1137, 1123.5, 1125	272	64	824
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1138, 1138, 1123.5, 1126	1438	834	4379
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	-, 4068, -, 4068	320	11	300
Feb 20	4146, 4148, 4088, 4102	22360	2669	89275
Mar 20	4186, 4186, 4130, 4144	2550	377	5605
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4160, 4228, 4106, 4106	480	33	580
Feb 20	4176, 4242, 4122, 4128	7880	830	26530
Mar 20	4194, 4258, 4120, 4130	2340	373	8605
Apr 20	4202, 4228, 4150, 4182	535	82	3165
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	789.1, 807.2, 787.9, 802.1	17320	1208	34960
Feb 28	787, 799.4, 785, 795.4	16470	1097	40980
Mar 31	783.4, 792.5, 779, 788.3	2110	139	8860
Apr 30	779, 779, 779, 779	10	1	210
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1268.7, 1271.1, 1251, 1253.6	165.24	406	223.56
Feb 28	1280, 1280, 1260.2, 1262.3	56.16	143	95.4
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
May 29	1220, 1222, 1220, 1221	0.72	2	1.8
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4290, 4300, 4211, 4226	1270	14	2290
Feb 20	4320, 4346, 4277, 4286	12020	914	12370
Apr 20	4316, 4335, 4287, 4301	8140	693	11930
May 20	4326, 4330, 4298, 4322	210	21	1510
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	900, 910, 900, 908.2	2710	151	3700
Feb 20	885.2, 895.8, 882.8, 892.2	24755	2775	55395
Mar 20	878.8, 884.8, 874.2, 882.6	5295	582	26965
Apr 20	869, 877, 867, 875.6	665	105	3270
May 20	868.4, 874.2, 868.4, 874.2	35	7	50
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4250, 4294, 4232, 4236	2985	218	6850
Feb 20	4214, 4256, 4202, 4234	34170	4065	185570
Mar 20	4232, 4262, 4214, 4242	12115	1707	109565
Apr 20	4250, 4280, 4236, 4256	3405	455	35525
May 20	4276, 4294, 4260, 4276	770	93	3555
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7204, 7204, 7186, 7200	110	13	170
Feb 20	7391, 7395, 7289, 7310	7910	1212	55385
Mar 20	7485, 7496, 7394, 7408	2390	352	11000
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4502, 4502, 4360, 4410	1180	41	310
Mar 20	4252, 4252, 4125, 4139	26630	1931	22850
Apr 20	4225, 4232, 4117, 4127	3820	357	4310
May 20	4235, 4239, 4130, 4150	1140	108	750
Jun 19	4200, 4200, 4200, 4200	20	2	20
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7440, 7440, 7440, 7440	25	1	25
Wheat-Kota NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2249, 2249, 2249, 2249	10	1	-
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	4080, 4080, 3937.4, 3951	5.9	57	6.3
Mar 13	3867.6, 3890, 3750, 3804.4	2.3	18	3.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6242, 6404, 6210, 6306	170	16	720
Apr 20	6920, 6988, 6830, 6935	1390	134	9120
May 20	6900, 6900, 6885, 6900	70	7	300
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15800, 15835, 15800, 15825	30	8	66
Mar 20	14995, 15055, 14870, 14910	738	238	1794
Apr 20	14840, 14880, 14710, 14745	252	70	894
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6390, 6390, 6182, 6246	1510	257	5325
Apr 20	6272, 6272, 6142, 6156	810	142	4525
May 20	6278, 6278, 6278, 6278	5	1	95
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	145.4, 145.4, 140, 142.65	4	4	2
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	140.95, 141.5, 140.5, 141.4	2928	1952	4644
Feb 28	141.55, 142, 141.55, 141.95	333	270	1562
Mar 31	142.05, 142.05, 142.05, 142.05	1	1	5
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	455.7, 456.55, 455.05, 455.55	9302.5	3319	13337.5
Feb 28	455.95, 456.45, 454.8

चीन की शरण में पाकिस्तान

पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर यही है कि उसे आतंकी गतिविधियों के लिए होने वाली फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए एफएटीएफ की तरफ से आंशिक अनुपालन रेटिंग मिले

आदिति फडणीस

धनशोधन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे सूची से पाकिस्तान को बाहर निकालने की पैरवी के लिए इस्लामाबाद के एक अधिकारियों का दल आजकल पेइचिंग में है। एफएटीएफ की बैठक 21 जनवरी को शुरू होगी।

पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी संभावना यह है कि अगर उसे यह प्रमाणपत्र नहीं मिला कि उसने धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए, तो उसे एफएटीएफ की तरफ से आंशिक अनुपालन रेटिंग मिल सकती है। एफएटीएफ ने अपनी कार्ययोजना में पाकिस्तान को 27 सिफारिशें लागू करने को कहा था। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कार्ययोजना का पूरी तरह अनुपालन करने के लिए एफएटीएफ की तरफ से ज्यादा समय मिल जाएगा।

पाकिस्तानी मीडिया का सरकारी सूत्रों के हवाले से कहना है कि भारत पाकिस्तान को काली सूची में डालने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है लेकिन इस्लामाबाद को उम्मीद है किचीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से नई दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की अगुआई आर्थिक मामलों के मंत्री हमद अजहर कर रहे हैं और इसमें नैशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, विदेश मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सीमा शुल्क विभाग, गृह मंत्रालय और फाइनैंशियल मॉनीटरिंग यूनिट (एफएमयू) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

पाकिस्तान ने एफएटीएफ द्वारा उठाए गए 150 सवालों के जवाब में 8 जनवरी को 650 पन्नों की समीक्षा रिपोर्ट भेजी थी। अब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल एफएटीएफ की कार्ययोजना की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देगा।

> चीन कह चुका है कि पाकिस्तान को सजा देने से एफएटीएफ के काम में बाधा आएगी

एफएटीएफ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान को चार महीने तक अपनी ग्रे सूची में रखेगा और अगर वह संस्था के 27 सूत्री कार्ययोजना पर उल्लेखनीय प्रगति करने में नाकाम रहा तो उसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान मीडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा, 'पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों, उनके सदस्यों को दी गई सजा, मदरसों की पंजीकरण प्रक्रिया, धनशोधन के खिलाफ उठाए गए कदम, आतंकवाद के वित्तपोषण की व्यवस्था को ध्वस्त करने और आतंकवादी संगठनों को पैसा हस्तांतरित करने के 500 से अधिक मामलों की जांच के बारे में एफएटीएफ को जानकारी देगा।' पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल साथ ही देश में धन शोधन रोधी कानून और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के नियमों को लागू करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के साथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट करने के बारे में किए गए प्रयासों की भी विस्तृत जानकारी देगा।

पाक के सरकारी सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को काली सूची में डलवाने के लिए पूरी कोशिश में है भारत

चीन कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान को सजा देने से एफएटीएफ के कामकाज में बाधा पहुंचेगी। उसने साथ ही साफ किया है कि वह पाकिस्तान को सजा देने के खिलाफ लड़ता रहेगा। अगर एफएटीएफ को लगता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए अब तक जो कदम उठाए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और उसे काली सूची में डाला जाता है तो इसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा। पिछले महीने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की तरफ से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) की 6 अरब डॉलर की दूसरी खेप मिली थी। उसने साथ ही चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं लेकिन जोखिम अब भी बरकरार हैं। पाकिस्तान के पास अब 17.6 अरब डॉलर विदेशी भंडार रह गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 10.9 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि दूसरे बैंकों के पास कुल 6.7 अरब डॉलर जमा हैं।

शाह की छाया से बाहर होंगे पार्टी के नए अध्यक्ष नड्डा

अर्चिस मोहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नया अध्यक्ष बनने पर जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का खंडन करने के लिए लोगों से संपर्क करें।

59 वर्षीय नड्डा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे और जून के मध्य में उनकी नियुक्ति भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हुई थी। भाजपा 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत का अनुसरण करती है और इसके अनुसार अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए था लेकिन वह गृहमंत्री बनने के बावजूद शाह सात महीने तक पार्टी अध्यक्ष के पद पर भी बने रहे। शाह के ही नेतृत्व में पार्टी झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में उतरी। शाह ने जुलाई 2014 में पार्टी अध्यक्ष की कमान तब संभाली थी जब केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह को भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था।

मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद लोगों को याद दिलाया कि नड्डा 1990 के दशक से ही उनके करीबी रहे हैं। मोदी उन दिनों हिमाचल प्रदेश में पार्टी के संगठनात्मक मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और नड्डा भाजपा युवा इकाई के प्रमुख थे। मोदी ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि वह नड्डा के साथ पार्टी के कामकाज के सिलसिले में दोपहिया वाहन से घूमा करते थे।

पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपने तीन साल के कार्यकाल में शाह की छाया से बाहर आना ही नड्डा की सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पार्टी के मामलों में शाह की पकड़ जारी रहेगी। इसकी वजह यह भी है कि हाल में जो नेता प्रदेश प्रभारी के तौर पर चुने गए हैं वे शाह के करीबी माने जाते हैं।

शांत स्वभाव वाले नड्डा पर्दे के पीछे ही रहकर काम करने में खुद को सहज पाते हैं और उनकी ख्याति पार्टी को जमीनी स्तर पर संगठनात्मक तरीके से मजबूत बनाने वाले नेता के तौर पर है। उन्हें अब न केवल इस साल के आखिर में पार्टी को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रखना है बल्कि मई 2021 में पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव की चुनौतियों के लिए भी मजबूती से खड़े रहना है।

नड्डा निर्विवाद रूप से पार्टी अध्यक्ष चुन लिए गए क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के बाद वही एकमात्र उम्मीदवार थे। शाह ने कहा कि भाजपा दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले इसी वजह से अलग है क्योंकि यहा किसी खास जाति या परिवार के लोग नेतृत्वकर्ता की भूमिका में नहीं आते हैं। नड्डा के पिता पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं

वैसे नड्डा का ताल्लुक किसी राजनीतिक परिवार से नहीं रहा है लेकिन उनकी शादी राजनीतिक परिवार में हुई है। उनकी सास जयश्री बनर्जी का उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा प्रभाव रहा है जो जबलपुर से भाजपा की पूर्व सांसद रही हैं और कई दफा मध्यप्रदेश में विधायक रहने के साथ-साथ राज्य की पूर्व मंत्री भी रही हैं।

फोटो: संजय शर्मा

जे पी नड्डा के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनका स्वागत करते प्रधानमंत्री मोदी

हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले नड्डा का लालन-पालन पटना में ही हुआ और वह पटना विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के साथ ही 1991 में भाजपा की युवा इकाई के प्रमुख बने। इसके बाद 1993 में हिमाचल प्रदेश में विधायक चुने गए और 2007 में राज्य में मंत्री बन गए।

अपने भाषण में कांग्रेस के नाम का जिक्र किए बगैर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध करने वालों का जिक्र करते हुए कहा, 'जिन्हें लोगों ने खारिज कर दिया है उनके पास सीमित तरीके ही बचते हैं ताकि वे झूठ फैला सकें। भाजपा के कार्यकर्ताओं को देश के लोगों से ताकत मिलती है। हमें उन लोगों से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है जो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे।' मोदी ने कहा, 'कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें निर्देशित करने वाले सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। इसी वजह से वे समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं।'

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में रोजना 10-15 रैलियों का आयोजन हो रहा है जिनमें 50,000 से एक लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं लेकिन मीडिया इन रैलियों को कवर नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह खेल जारी रहेगा ऐसे में कार्यकर्ताओं को लोगों से सीधे तौर पर संपर्क साधने की जरूरत है।

पाक में रोटी का संकट बढ़ा, गेहूं आयात होगा

रॉयटर्स

पाकिस्तान में आटे की आपूर्ति में कमी के संकट से जूझ रही प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने सोमवार को 3,00,000 टन गेहूं आयात की मंजूरी दे दी। पिछले हफ्ते आटा और ब्रेड की कीमतों में तेजी आई और यह दुकानों और थोक बाजार से लगभग गायब ही हो गया। ब्रेड बनाने वालों ने पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करते हुए नियंत्रित कीमतों पर गेहूं बेचने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। इस्लामाबाद के बगल के शहर रावलपिंडी के एक दुकानदार शेराज खान ने कहा, 'अगर मैं ज्यादा कीमत में आटे की बोरी खरीदता हूं तो 8 रुपये में ब्रेड बेचना मेरे लिए संभव नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से गैस की कीमतों में भी कई गुना की तेजी आ चुकी है।' उन्होंने बताया कि उनके गैस संचालित ओवन के बिल में चार गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊर्जा मूल्य नियामक ने एक बार और कीमत में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है और अधिकारियों के मुताबिक इसकी मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।

वित्त मंत्री ने एक बयान में कहा कि सोमवार को आयात का फैसला आर्थिक समन्वय परिषद ने किया और इसकी पहली खेप 15 फरवरी तक आने की संभावना है। वित्त मंत्री ने एक बयान में कहा कि इस अनाज के लिए नियामकीय शुल्क में छूट दी जाएगी जिसका आयात 31 मार्च तक होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान किस देश से या किन देशों से गेहूं का आयात करेगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि निजी क्षेत्र के खरीदार जहां से चाहें वहां से गेहूं का आयात कर सकते हैं। पाकिस्तान के सांख्यिकीय ब्यूरो का कहना है कि 2018 से जून 2019 के बीच 600,00 टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात किया गया। हालांकि सरकार ने पिछले साल जुलाई में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया इसके बावजूद अक्टूबर 2019 तक विदेश में 48,000 टन गेहूं का निर्यात किया गया। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले सीजन में खराब पैदावार के बाद गेहूं का निर्यात करने का कोई अर्थ नहीं था। ऐसे में प्रतिबंध के बावजूद निर्यात करने के कदम की जांच होनी है।

- **पाकिस्तान में आटे की हो गई है भारी कमी**
- **पिछले हफ्ते आटा, ब्रेड की कीमतों में आई तेजी**
- **पहली खेप 15 फरवरी तक पहुंचने की है उम्मीद**
- **पिछले सीजन में खराब पैदावार के बावजूद निर्यात था जारी**

विपक्षी दल से नेता ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कुछ लोगों ने अरबों रुपये बना लिए और उनका कहना है कि उन्हें संदेह है कि गेहूं का संकट किसी घोटाले का नतीजा हो सकता है। गेहूं की कीमतें बढ़ने से इमरान सरकार की तीखी आलोचना हो रही है जिन पर उनकी गठबंधन सरकार की एक प्रमुख पार्टी के मंत्रिमंडल छोड़ने से पहले से ही दबाव की स्थिति बनी हुई है। दूसरे सहयोगी दलों ने भी सरकार के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं।

पाकिस्तान कृषि आधारित देश है जो सामान्यतौर पर आबादी की जरूरतें पूरी करने भर फसलें उगा लेता है। विपक्षी दलों और कुछ अर्थशास्त्रियों ने जांच की मांग करते हुए कहा है कि आखिर पिछले साल तक जब देश गेहूं का निर्यात कर रहा था तब आखिर गेहूं आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

देश के 63 अरबपतियों के पास आम बजट से ज्यादा संपत्ति

भारतीय अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी अधिक संपत्ति है। इन एक फीसदी सबसे अमीर लोगों के पास देश की कम आय वाली 70 फीसदी आबादी यानी 95.3 करोड़ लोगों की तुलना में चार गुना से भी अधिक संपत्ति है। एक नए अध्ययन में सोमवार को इसका खुलासा किया गया।

दुनिया की बात की जाए तो 2,153 अरबपतियों के पास दुनिया की निम्न आय वाली 60 प्रतिशत आबादी यानी 4.6 अरब लोगों की संपत्ति से भी अधिक संपत्ति है। मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन ऑक्सफेम ने विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक से पहले यहां टाइम टू केयर अध्ययन जारी किया है जिसमें यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अध्ययन में कहा गया कि विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है और पिछले दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है। हालांकि, पिछले साल इन अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति में कमी आई है।

अध्ययन में भारत के संदर्भ में कहा गया कि देश के 63 अरबपतियों के पास 2018-19 के 24,42,200 करोड़ रुपये के आम बजट की तुलना में अधिक संपत्ति है। ऑक्सफेम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा, 'असमानता को दूर करने की दृढ़ नीतियों के बिना अमीर और गरीब की खाई को पाटा नहीं जा सकता है। कुछ ही सरकारें हैं जो ऐसा करने को प्रतिबद्ध हैं।'

बेहर ने कहा, 'हमारी अक्षम अर्थव्यवस्थाएं आम लोगों की कीमत पर अरबपतियों और बड़ी कंपनियों की जेबें भर रही हैं। आश्चर्य नहीं, ऐसे भी सवाल उठने लगे कि क्या अरबपतियों को होना चाहिए।' रिपोर्ट के अनुसार, एक घरेलू महिला कामगार को किसी प्रौद्योगिकी कंपनी के शीर्ष सीईओ की एक साल की कमाई के बराबर कमाने में 22,277 साल लगेंगे। प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ प्रति सेकंड 106 रुपए की औसत कमाई करते हैं। ऐसे में एक घरेलू कामगार जितना एक साल में कमा पाती है, प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ 10 मिनट में ही उससे अधिक कमाई कर लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाएं व लड़कियां रोजाना 3.26 अरब घंटे का ऐसा काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम 19 लाख करोड़ रुपये के योगदान के बराबर है, जो कि 2019 के भारत के 93 हजार करोड़ रुपये के शिक्षा बजट का 20 गुना है। बेहर ने कहा कि मौजूदा आर्थिक तंत्र में महिलाएं और लड़कियां ही सबसे कम फायदा पाती हैं।

चित्रांकनः अजय मोहंती

ऑक्सफेम ने कहा कि सरकारें अमीर वर्ग और कंपनियों से बेहद कम कर वसूल रही हैं, जिससे राजस्व संग्रह कम हो रहा है। यह राजस्व गरीबी और असमानता को दूर करने के काम आ सकता था। अध्ययन के अनुसार, विश्व के 22 सबसे अमीर लोगों के पास अफ्रीका की सभी महिलाओं से अधिक संपत्ति है। इसमें कहा गया कि यदि अमीर वर्ग अपनी संपत्ति पर महज 0.5 प्रतिशत की दर से अगले 10 साल के लिए अतिरिक्त कर का भुगतान करे तो यह बुजुर्गों व बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में 11.7 करोड़ रोजगार के मौके देने के लिए जरूरी निवेश के बराबर होगा।

दावोस में देश के 100 से अधिक कारोबारी

स्विट्जरलैंड का खूबसूरत स्की रिसॉर्ट शहर दावोस विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 50वीं सालाना बैठक के लिए तैयार है। सोमवार से दावोस में शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक में वैश्विक कारोबारियों, उद्यमियों और राजनेताओं के साथ ही भारत से भी 100 से अधिक कारोबारी और राजनेता आर्थिक महत्व तथा भू-राजनीतिक मामलों पर चर्चा में शामिल होंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ अफगानिस्तान, आयरलैंड, फिनलैंड, ब्राजील, इराक, सिंगापुर समेत अन्य देशों के राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं।

देश से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तीन मुख्यमंत्रियों अमरिंदर सिंह, कमलनाथ और बी.एस.येदियुरप्पा समेत भारतीय कंपनियों के 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। चर्चा के लिए चुने गए विषयों में मानसिक स्वास्थ्य अहम रहेगा और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पडुकोणे इस विषय पर बोलेंगी। *एजेंसियां*

गहरी साजिश के दिख रहे लक्षण

जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह की गिरफ्तारी से पुलवामा हमला फिर सुर्खियों में

आदिति फडणीस

करीब एक वर्ष पहले 14 फरवरी को देश उस समय स्तब्ध रह गया था जब 350 किलोग्राम विस्फोटक से भरे एक एसयूवी वाहन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस को पुलवामा में टक्कर मार दी। इस हमले में 44 जवान मारे गए। इस हमले की कई गुत्थियां आज भी अनसुलझी हैं।

यह बस सीआरपीएफ के 78 वाहनों के काफिले में शामिल थी। तो फिर उस खास बस को ही क्यों चुना गया? यह एसयूवी कहां से आई और इसे खरीदने के लिए पैसे किसने दिए? बारहवीं की परीक्षा देने जा रहे 22 साल के आदिल अहमद डार को किसने इस हमले के लिए प्रेरित किया? सबसे बड़ी बात कि 350 किग्रा विस्फोटक कहां से आया? इसमें किसने मदद की और किसी की जानकारी के बिना इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कैसे जमा हुआ?

उस समय देश के चुनाव का बुखार छाया हुआ था। बालाकोट पर हुआ सर्जिकल हमला ऐसा जवाब था जिससे साबित हुआ कि देश में दमदार सरकार है और इससे विपक्ष पूरी तरह रक्षात्मक हो गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार इसी निर्णायक कार्रवाई के दम पर सत्ता में लौटी थी। लेकिन कई सवालों के जवाब अब भी नहीं मिला है।

पुलवामा हमला हाल के दिनों में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अब जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारी दविंदर सिंह की गिरफ्तारी से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खासकर, हमलावर का साथ देने वालों की भूमिका को लेकर।

पुलिस ने 11 जनवरी को 57 साल के पुलिस उपायुक्त दविंदर सिंह को कुलगाम के मीर बाजार से हिजबुल मुजाहिदीन के दो आंतकवादियों नवीद बाबा और अल्ताफ के साथ गिरफ्तार किया। उनके साथ एक वकील भी था जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम करता है।

सिंह को 13 जनवरी को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसको हिरासत में 48 घंटे हो चुके थे। अब इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर सिंह उन लोगों की संगत में कैसे पहुंच गया, जिन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी उस पर थी। उस पर आतंकवाद और पुलवामा हमले में भी शामिल होने के आरोप लगने लगे। हालांकि आतंकवादरोधी विशेषज्ञों का कहना है कि इस आरोप में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि पुलवामा हमले से करीब छह महीने पहले ही उसका वहां से तबादला कर दिया गया था। चूंकि आरडीएक्स एक अस्थायी विस्फोटक है, इसलिए इसका लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है।

चित्रांकनः बिनय सिन्हा

कश्मीर में रह चुके 1976 बैच के भारतीय पुलिस सेवा सेवा (आईपीएस) के असम-मेघालय काडर के अधिकारी कुलबीर कृष्णन ने कहा कि समस्या व्यवस्थागत है। उन्होंने कहा, 'आप एक गलत आदमी के लिए जम्मू-कश्मीर के 60 हजार पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन यह साफ है कि सिंह के पीछे किसी का हाथ है, अन्यथा आप इतने लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर सकते हैं। जो भी उनकी मदद कर रहे थे, चाहे वे पुलिस अधिकारी हैं, राजनेता हैं या प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।'

सच्चाई यह है कि आंतकवादियों से लड़ने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल एक आंतकवादी निरोधक रणनीति है। यह बहुत पुरानी रणनीति है। पंजाब के दिग्गज पुलिस अधिकारी केपीएस गिल ने राज्य में यही रणनीति अपनाई थी जब भारत ने उग्रवादी संगठनों के बीच फूट डालने के लिए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की मदद की थी। पूर्वोत्तर में कई पुलिसकर्मी विद्रोही बन गए थे। मेघालय में एक पुलिकर्मी ने गारो नैशनल लिबरेशन आर्मी बनाई थी।

चैंपियन संगमा और उनके 'आर्मी चीफ' सोहन डी शीरा सशस्त्र गतिविधियां चलाते थे और पैसों की उगाही करते थे। संगमा को बांग्लादेश के अधिकारियों ने पकड़कर सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया था। शीरा एक मुठभेड़ में मारा गया।

आतंकवादरोधी विशेषज्ञों का कहना है कि सशस्त्र समूहों को हथियार, पैसा और दूसरी सुविधाएं देना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जायज गतिविधि का हिस्सा है। संभव है कि सिंह ने ऐसी ही शुरुआत की हो और फिर अपना दायरा बढ़ाया हो।

जम्मू-कश्मीर में जब गुलाम नबी आजाद/मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी तो उस समय सिंह सुर्खियों में आया था। उस समय एक महिला ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में गुहार के खिलाफ उगाही करने का आरोप लगाया। उसका आरोप था कि सिंह ने उसके पति को बंधक बना रखा है और उसकी रिहाई के लिए पैसे मांग रहा है। न्यायालय ने सिंह को फटकार लगाई। लेकिन कुछ ही महीनों में सिंह को प्रोन्नत कर दिया गया।

इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले की गई है जिसे आरोपपत्र तैयार करने में चार महीने का समय लग सकता है। तब तक सिंह को कठघरे में खड़ा करने से बचा जाना चाहिए। लेकिन बीमारी व्यवस्थागत है, सिंह तो केवल उसका लक्षण है।